न्यू देहली पोस्ट

■ वर्ष 13 ■ अंक 13 रविवार (साप्ताहिक) 6 अप्रैल 2025 ■ पृष्ठ 16 ■ मूल्य 5 रुपये

सिकंदर' में सलमान-रश्मिका का रोमांटिक अंदाज

अंदर विशेष

'सौगात-ए-मोदी' से क्या बदलेगा मुस्लिम वोटरों का मिज़ाज?

पृष्ठ 3 पर

क्या चाचा के साथ फिर लौटेंगे भतीजा?

पृष्ठ 5 पर

बंगाल में दीदी को हराने की बड़ी तैयारी

पृष्ठ 7 पर

अब अय्यपा मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर नया विवाद

पृष्ठ 11 पर

30 अप्रैल से होगा चार धाम यात्रा का आगाज

पृष्ठ 12 पर

अमेरिका में बड़ा चुनावी रिफॉर्म, वोटिंग के लिए सिटीजनशिप प्रूफ अनिवार्य

पृष्ठ 15 पर

न्यायपालिका हुई दागदार!

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले यह बी ही कहा था कि ''सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इस फैसले से एक गंभीर सवाल उठता है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान है? यह मामला तब महत्वपूर्ण हो जाता है, जब हम मौजूदा स्थिति की जांच करते हैं, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में माननीय जजों की कमी है और लगातार समस्याओं के बावजूद पिछले कई सालों से नए जजों की नियुक्ति नहीं हुई है।

न्यू देहली पोस्ट डेस्क

सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने के साथ ही उनको मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को भेजे जाने के कॉलेजियम के फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया, ''हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अधिवक्ता न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरण के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, हम इस संबंध में लखनऊ में बार एसोसिएशन को प्रस्ताव भेज रहे हैं।

तिवारी ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश को न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा जांच की तत्काल अनुमति देनी चाहिए और साथ ही जरूरत पड़ने पर न्यायमूर्ति वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे पूर्व,

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने प्रधान न्यायाधीश से सरकार से न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करने की मांग की।

यह भी बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले यह बी ही कहा था कि ''सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इस फैसले से एक गंभीर सवाल उठता है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान है? यह मामला तब महत्वपूर्ण हो जाता है, जब हम मौजूदा स्थिति की जांच करते हैं, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में माननीय जजों की कमी है और लगातार समस्याओं के बावजूद पिछले कई सालों से नए जजों की नियुक्ति नहीं हुई है।

शेष १ पर

बांग्लादेश में हो सकता है फिर तख्तापलट या फिर हसीना की वापसी!

न्यू देहली पोस्ट

बांग्लादेश में गुपचुप तरीके से जो कुछ होता दिख रहा है उससे साफ़ है कि भारत के पडोसी देश बंगलादेश में एक बार फिर से कोई बड़ा बदलाव हो सकता है और बंगलादेश की राजनीति बदल सकती है। जानकारी के मुताबिक़ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ अब बड़ा माहौल तैयार हो रहा है और इसके साथ ही जनता की नजरों में वहां की सेना भी काफी बदनाम होती जा रही है। बांग्लादेश के लोगों के मन में यह बात बैठती जा रही है कि बंगलदेश की सेना किसी भी सूरत में फिर से निर्वासित शेख हसीना को पदस्थापित करना चाहती है और उसे बचाने में लगी है।

बड़ी बात तो यह है कि शेख हसीना के प्रति वहां की सेना का कितना झुकाव है भी या नहीं लेकिन शक के दायरे में वहां की सेना तो आ ही गई है और अब लोग सेना के खिलाफ भी बोलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब कई बड़े बदलाव की सम्भावना बढ़ती जा रही है। सेना की संभावित भूमिका भी अब बढ़ सकती है और इस दिशा में कुछ बड़े कदम भी उठाये जाने के संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जल्द ही सेना के हवाले हो सकता है।

सूत्रों के हवाले से इंडिया टुडे ने कहा है कि सेना प्रमुख (सीएएस) जनरल वकर-उज़-ज़मान के नेतृत्व में देश की सेना ने बीते सोमवार को एक आपातकालीन बैठक की, जिससे आसन्न कठोर कार्रवाई के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। इस उच्चस्तरीय बैठक में पांच लेफ्टिनेंट जनरल, आठ मेजर जनरल (जीओसी), स्वतंत्र ब्रिगेड के कमांडिंग अधिकारी और सेना मुख्यालय के अधिकारियों सहित प्रमुख सैन्य अधिकारियों ने भाग लिया है

शेष १ पर

पीएम मोदी की एक और तूफानी ऐलान धराशायी

न्यू देहली पोस्ट

आगे बढे इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट पर गौर करने की जरूरत है। वे लिखती हैं कि ''वो सी प्लेन याद है, जिसपर अक्टूबर 2020 में मोदी जी सवार हुए थे, साबरमती रिवर फ्रंट पर खूब शोशेबाजी हुई थी, वीडियो बने, फोटो खीचीं गई। लेकिन अब गुजरात सरकार ने बताया है कि उसमें 19.50 करोड़ रुपए झोंके गए, पर ऑपरेटर भाग गया और वो तबसे जस का तस पड़ा हुआ है।'' एक दूसरे ट्वीट में कहा गया है कि ''बड़ी धूमधाम से मोदी जी ने गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की थी।

इस सेवा के लिये 198 करोड़ का जहाज खरीदा गया। 62 करोड़ पायलट, स्टाफ और मेंटेनेंस पर खर्च किये गये।इसके अलावा करोड़ों प्रचार पर खर्च हुए।ये सेवा 21 अक्टूबर 2020 में शुरू हुई और 6 महीने बाद अप्रैल 2021 में बंद हुई। 4 साल से मोदी ने इस सी प्लेन की ओर मुड़कर नहीं देखा।पर आज भी ये बंद योजना सरकारी फाइलों पर जारी है और स्टाफ, देखभाल का मोटा खर्च जनता के टैक्स के पैसे से उठाया जा रहा है।

शेष १ पर

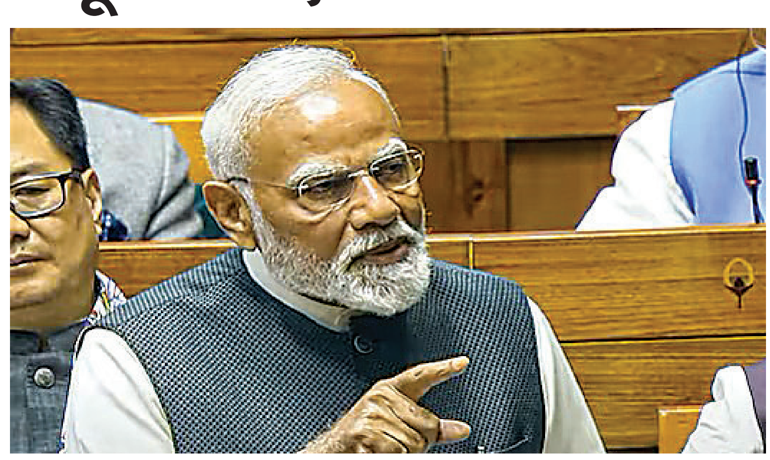

न्यायपालिका हुई...

यह भी गंभीर चिंता का विषय है कि बार के सदस्यों को पदोन्नत करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय बार से कभी भी परामर्श नहीं किया गया। पात्रता पर विचार करना मानक के अनुरूप नहीं लगता। कुछ कमी है, जिसके कारण भ्रष्टाचार हुआ है। परिणामस्वरूप, "न्यायपालिका में जनता के विश्वास" को बहुत नुकसान पहुंचा है।''

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने यह उपरोक्त पत्र सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को लिखा है। यह पत्र इसलिए लिखा गया कि पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास से 15 करोड़ की नकदी पाई गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया।

यह बात और है कि सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच तो चल रही है लेकिन शीर्ष अदालत ने कोई त्वरित जांच करने से अभी मना कर दिया है। यह मामला संसद में भी उठ रहा है लेकिन वहां भी सब कुछ मौन ही है। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन एक बात तो साफ़ है कि

हमारे देश की न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कोई सोंच भी नहीं सकता कि देश का कोई जज अपने घर में 15 करोड़ की नकदी रखता है। आखिर ये पैसे आये कहाँ से ? फिर जहाँ से आये उसके बदले में जस्टिस वर्मा ने क्या कुछ किया ?

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर होली के दिन आग लग गई थी। जस्टिस वर्मा घर से बाहर थे। आग बुझाने के दौरान दमकलकर्मियों और पुलिस को भारी मात्रा में नकदी मिली। इसके बाद इसे पुलिस को सूचित किया गया और फिर इस मामले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक बुलाई गई और तत्काल प्रभाव से जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। वर्मा वही से दिल्ली हाई कोर्ट आये थे। बाद में जांच के दौरान यह भी पता चला कि नोटों के बंडल जला दिए गए थे और भारी मात्रा में अधजले नोट के वीडियो सामने आये थे। लेकिन यह सब किया किसने और क्यों ,आज तक इस पर पर्दा चढ़ा हुआ है।

अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले को महज स्थानांतरण से नहीं दबाया जा सकता है। न्यायपालिका में देश का विश्वास बनाए रखने के लिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि यह पैसा किसका है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निशमन विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो से बेहतर काम कर रहा है।

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जज के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलना बहुत गंभीर मामला है और इसे उनका तबादला करके दबाया नहीं जा सकता। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "जस्टिस वर्मा उन्नाव दुष्कर्म केस और कई अन्य गंभीर मामलों की सुनवाई कर रहे थे। न्यायपालिका में देश का विश्वास बनाए रखने के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि यह पैसा किसका है और जज को क्यों दिया गया।" उन्होंने कहा, "न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाते हुए एक पूर्व सीजेआई ने कहा था कि कानून अंधा नहीं है, यह सबको समान रूप से देखता है। इस मामले में यह बात साबित भी होनी चाहिए।"

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "खैर जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, अगर वह सही है तो यह बहुत गंभीर मामला है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मामले का संज्ञान लिया है। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस मामले में क्या फैसला लेता है।"

मामले पर भाजपा ने कहा कि पार्टी को अदालतों के मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और सीजेआई पहले से ही इस मामले से अवगत हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले पर निर्णय ले लिया है, जिससे उच्च न्यायपालिका पर लोगों की असहज नजर पड़ रही है।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर मिले कैश की बात नहीं कि बल्कि उन्होंने न्यायपालिका से जुड़ी कई और बातों को भी हाइलाइट किया है। सिब्बल ने न्यायतंत्र के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीर बताते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। कपिल सिब्बल ने कहा,'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। यह बात देश के कई वरिष्ठ वकीलों ने पहले भी कही है। यह समस्या सालों से चली आ रही है। यह कोई ऐसी बात नहीं है, जिसे देश की सीनियर काउंसिल और वकीलों ने पहली बार उठाया है। यह सब सालों से चला आ रहा है।'

सिब्बल ने आगे कहा,'सुप्रीम कोर्ट को नियुक्ति प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और सावधानी के साथ पूरी करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर ध्यान देना शुरू करे कि नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है।'

भ्रष्टाचार कम होने के दावों पर सवाल उठाते हुए सिब्बल ने कहा,'भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा है और पीएम मोदी के भ्रष्टाचार कम होने के दानों के बावजूद यह बढ़ा है। जब लोकपाल को लेकर प्रदर्शन हुआ था, तब सभी राजनीतिक दल कांग्रेस पर आरोप लगाते थे। इसके बाद लोकपाल बिल आ गया, लेकिन क्या हुआ। सरकार गिरा दी गई और इसके बाद कुछ नहीं किया गया। न केजरीवाल ने कुछ किया और न ही प्रधानमंत्री ने कुछ किया। बस एक लोकपाल को बैठा दिया और वो तो आप देख ही रहे हैं कि क्या करते हैं।'

बांग्लादेश में हो सकता है फिर...

क्या एक और तख्तापलट की तैयारी है?

सूत्र संकेत देते हैं कि सेना राष्ट्रपति पर आपातकाल की स्थिति घोषित करने या यूनुस को सीधे सत्ता से हटाने का दबाव बना सकती है।सैन्य नेतृत्व वाली राष्ट्रीय एकता सरकार की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। सेना के बढ़ते असंतोष को विभिन्न राजनीतिक दलों और छात्र नेताओं के हालिया विरोधों ने हवा दी है, जिन्होंने सेना के प्रभाव की खुले तौर पर आलोचना की है।अशांति ने सेना के भीतर के वर्गों को असंतोष को दबाने के उपायों की खोज करने के लिए उकसाया है।जवाब में, बांग्लादेश की सेना ने 21 मार्च से ढाका में सुरक्षा अभियान तेज कर दिया है, संयुक्त बलों की तैनाती की है, गश्त बढ़ाई है और चौकियां स्थापित की हैं।हाल के हफ्तों में सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर व्यापक अभियान ने संकट को और हवा दे दी है।

उधर ,फ्रांस में रहने वाले बांग्लादेशी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पिनाकी भट्टाचार्य ने चरमपंथियों और छात्रों से सेना प्रमुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आग्रह किया है, उन पर भारत से प्रभावित होने का आरोप लगाया है। इस बीच, छात्रों के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने आरोप लगाया है कि सेना शेख हसीना की अवामी लीग को फिर से संगठित करने की साजिश कर रही है .हालांकि सेना इस दावे का खंडन किया है।

यूनुस की चीन यात्रा जांच के घेरे में : इस उथल-पुथल के बीच, अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस जल्द ही चीन की यात्रा करने वाले हैं। यह यात्रा, जो संभावित रूप से चीन-बांग्लादेश संबंधों को नया रूप दे सकती है। भारत की इस यात्रा पर पैनी निगाह है। दक्षिण एशिया में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, यूनुस की यात्रा को एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

क्या शेख हसीना वापसी के लिए तैयार है

उधर एक गुप्त तैयारी यह भी चल रही है कि शेख हसीना की सत्ता में वापसी हो जाए। यूनाइटेड स्टेट्स अवामी लीग के उपाध्यक्ष और हसीना के करीबी सहयोगी डॉ. रब्बी आलम ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की राजनीतिक वापसी आसन्न है।13 मार्च को एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, आलम ने यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि हसीना को हटाने के लिए युवा पीढ़ी को "बहकाया" गया है।उन्होंने यूनुस से पद छोड़ने और अपनी पिछली भूमिका में लौटने का आह्वान किया, उन्होंने दावा किया कि हसीना की बहाली अपरिहार्य है।

बांग्लादेश के लिए आगे क्या है?

सैन्य तनाव बढ़ने, यूनुस के नेतृत्व की घेराबंदी और हसीना के समर्थकों द्वारा उनकी वापसी के लिए दबाव डालने के साथ, बांग्लादेश एक चौराहे पर खड़ा है।क्या सेना औपचारिक रूप से नियंत्रण लेगी, यूनुस सत्ता पर काबिज रहेंगे या हसीना नाटकीय वापसी करेंगी, यह देखना अभी बाकी है।

पीएम मोदी की एक...

हैरत ये है कि मोदी के कहने पर ये योजना झटपट शुरू हुई और बिना ठोस इकोनॉमिक वाइबिलिटी के इसे लांच कर दिया गया।''

गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने केवडिया से सी प्लेन के जरिये उड़ान भरकर साबरमती पहुंचे थे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह थी कि तब गुजरात विधान सभा का चुनाव चल रहा था और दो चरण के चुनाव भी हो चुके थे। इसके बाद मोदी की तरफ से यह सब तमाशा किया गया। लेकिन यह तमाशा कोई मामूली नहीं था। भोपू मीडिया को पहले मैनेज किया गया और फिर करोड़ खर्च प्रचार पर किये गए। देश भर के अखबारों और चैनलों में इसके कई दिनों तक विज्ञापन चलते रहे। टीवी डेबिट हुए और बड़े -बड़े आर्टिकिल भी लिखे और लिखवाये गए। यह एक ऐसा तमाशा था मानो देश के भीतर कोई बड़ी क्रांति होने जा रही है। कोई बड़ी उपलब्धि देश को मिलने जा रही है।

पीएम मोदी ने इस सी प्लेन योजना की शुरुआत उड़ान योजना के तहत किया था। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। यानी देश क्ले आम जानो के लिए सी प्लेन की शुरुआत की गई थी। कहा तो यह भी गया था कि भारत सरकार कई रूट पर सीप्लेन शुरू करने की योजना बना रही है। आने वाले समय में देश की कई अन्य रूटों पर भी सी प्लेन सेवा शुरू हो सकती है। यह भी कहा गया कि सरकार की योजना अगर तय समय से जमीन पर उतर गई तो दिल्ली के युमना रिवर फ्रंट से प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या के लिए आप सी प्लेन में उड़ान भर पाएंगे।

आनन फानन में देश के कई हिस्सों से इस सी प्लेन को चलाने की बात की गई। जहाजरानी यानी पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला सीप्लेन सेवा के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बी ही आमंत्रित किया। तबके पोर्ट्स, शिपिंग और वाटर वेज मंत्री मांडवीय ने सी प्लेन के प्रस्तावित रूट की जानकारी भी दी। उन होने यह भी कहा कि दिल्ली जयपुर, दिल्ली उदयपुर, दिल्ली जोधपुर और दिल्ली बद्रीनाथ की यात्रा भी सी प्लेन से की जाएगी।

दावे यह भी थे कि इन रूटों पर सीप्लेन सेवा उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत संचालित की जा सकती है। इस स्कीम के तहत आम लोगों के लिए यात्रा किफायती होती है। मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए एक हब और स्पोक मॉडल का उपयोग करने की योजना बनाई। बता दें कि अहमदाबाद रिवर फ्रंट से केवड़िया तक के लिए स्पाइसजेट कंपनी ने सी प्लेन सेवा दी थी यह भी बता दें कि जिस प्लेन से पीएम मोदी केवडिया से साबरमती तक उड़कर तमाशा किये थे उस सी प्लेन का निर्माण 1971 में कनाडा में हुआ था। कनाडा से इस सी प्लेन को मालदीप लाया गया था और मालदीप से इस सी प्लेन को भारत लाया गया। भारत में इस सी प्लेन को संचालित करने की जिम्मेदारी स्पाइस जेट को दिया गया क्योंकि वह इस तरह के सी प्लेन का संचालन करता रहा है। इस सी प्लेन को चलाने के लिए वाटर एरोड्रम का निर्माण किया गया जहाँ से सी प्लेन को उड़ान भरना होता है। इसके साथ ही इसकी पार्किंग की व्यवस्था की गई। कई कर्मचारी रखे गए। कुल मिलकर यह सी प्लेन लगभग छह महीने तक चला होगा और कोई सौ से कुछ ज्यादा लोगों ने इसका लाभ भी उठाया था। इसके बाद इस सी प्लेन को मालदीव भेज दिया गया। पहली बार 2023 में इस सी प्लेन के बाड़े में बड़ा खुलासा हुआ। जब गुजरात विधान सभा में कांग्रेस के एक विधायक ने इस सी प्लेन के बारे में जानकारी सरकार से मांगी। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवानिया ने विधानसभा में गुजरात सरकार से सवाल पूछा था जिसका लिखित में जवाब देते हुए गुजरात सरकार ने स्वीकार किया कि सी-प्लेन सेवा को बंद कर दिया गया है। दरअसल सी-प्लेन की शुरुआत से ही उसमें अड़चनें आनी शुरू हो गई थीं। कुछ-कुछ दिनों के बाद यह प्लेन सेवा बार-बार बाधित हो रही थी। जिसके बाद सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया।

गुजरात सरकार ने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक इस सक्सी प्लेन पर तब तक 13 करोड़ 15 लाख रुपये खर्च हो चुके थे। यह सब रख रखाव और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हुए थे। इसके एक साल बाद उसी गुजरात विधान सभा में विधायक परमार ने फिर से सी प्लेन के बारे में जानकारी मांगी तो चौंकाने वाले जबाव सामने आये। जानकारी मिली कि इस सी प्लेन पर अब तक 260 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इस खर्च में 158 करोड़ सी प्लेन पर खर्च हुए जबकि 62 करोड़ रखरखाव और वेतन भत्ते पर खर्च किये गए। याद रहे यह सी प्लेन 6 महीने भी उड़ान नहीं भर सका था। यह भी बता दें कि जब इस सी प्लेन का उद्घाटन हुआ था तो इसके प्रचार पर भी लगभग 19 करोड़ से ज्यादा खर्च किये गए थे। कमाई कितनी हुई इसकी जानकारी आप खुद ही लगा सकते हैं।

यानी यह सी प्लेन छह महीने चलने के बाद आज तक बंद है लेकिन इस पर खर्च अभी भी जारी है। कह सकते हैं कि पीएम मोदी की यह योजना भी ठंढे बस्ते में चली गई। आज कोई भी मीडिया इसके बारे में जानकारी नहीं लेने को तैयार नहीं है। देश के पैसों की बर्बादी कितनी हुई यह तो एक बानगी भर है लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस सी प्लेन को लेकर प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वह भी सही नहीं था। उन्होंने कहा था कि देश में पहली बार उन्होंने सी प्लेन की शुरुआत की है। पीएम का यह दावा भी गलत ही साबित होता है। सच तो यह है कि इस तयारह के सी प्लेन का उपयोग देश के कई राजा महाराजा भी करते रहे हैं। ग्वालियर और हैदराबाद के निजाम के पास भी ऐसे सी प्लेन थे जिसके जरिये वे देश के भीतर यात्रा करते थे। ग्वालियर के राजा तो तेघड़ा बाँध से इस सी प्लेन को उड़ाते थे और दिल्ली तक आते थे। लेकिन तब इसका नाम हुड्रो प्लेन कहा जाता था।

इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के समय भी इस तरह के के सी प्लेन का उपयोग किया जाता था और इसकी गवाही देश के बड़े नेता और ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे बीजू पटनायक भी कर गए थे। पटनायक एक ट्रेंड पायलट थे और दूसरे विश्व युद्ध के समय वे अंग्रेजों के लिए युद्ध में शामिल भी हुए थे। 1979 में एक बार ग्वालियर में ही इस बात का खुलासा किया था कि वे सी प्लेन के जरिये युद्ध स्थल पर जाया करते थे और लौटकर ग्वालियर के ही तेघड़ा डैम पर उतारकर पानी और तेल जहाज में लेते थे। ऐसे में साफ़ है कि सी प्लेन के बारे में जो कह गए थे वे सब झूठ पर आधारित थे।

सी प्लेन को उड़ने वाली नावों के रूप में जानते हैं, क्योंकि विमान का एक हिस्सा नाव के आकार का होता है। सी प्लेन ऐसा विमान है जो पानी की सतह और हवा दोनों ही जगह आसानी से उड़ान भर सकता है। इसे एंफीबियस कैटेगरी वाला प्लेन कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार एंफीबियन उस वर्ग को कहते हैं जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सके.यह छोटे फिक्स्ड विंग वाला विमान है जो जलाशय, पथरीले उबड़-खाबड़ जमीन और घास पर भी उतर सकता है। सी प्लेन में पानी में लैंडिंग और टेक-ऑफ करने की क्षमता होती है। सी प्लेन को पानी में उतरने के लिए छह फीट की न्यूनतम गहराई की जरूरत होती है। उड़ान भरने के लिए कम से कम 300 मीटर के रनवे और पानी की सतह की जरूरत होती है।

सी प्लेन दो तरह के होते हैं फ्लोट प्लेन्स और फ्लाइंग बोट। गुजरात के केवड़िया में शुरू समुद्री विमान सेवा के लिए फ्लोटिंग बोट (फ्लोटिंग जेटी) लाई गई थी। यह जेटी 9 मीटर चौड़ी और 24 मीटर लंबी थी। इस जेटी का कुल वजन 102 टन है। इस ट्विन ऑट्टर 300 सी-प्लेन की टंकी 1419 लीटर ईंधन से फुल हो जाती है। और महज 272 लीटर ईंधन में ये एक घंटे तक उड़ सकता है.इसमें पीटी 61-32 ट्विन टर्बो इंजन लगाया गया है।

न्यू देहली पोस्ट
30 मार्च 2025
संपादकीय कार्यालय : मुद्रक व प्रकाशक आशीष कुमार द्वारा विभा पब्लिकेशन डी-160 बी, सेक्टर-7, नोएडा से मुद्रित एवं 262ए, सेक्टर-4, वैशाली गाजियाबाद से प्रकाशित। RNI NO. UPHIN/2013/49239
संपादक : आशीष कुमार, **प्रसार प्रबंधक** : दशरथ सिंह
Postal registration Number: UP/GBD-181/2013-15, **हमसे संपर्क करें** : postnewdelhi@gmail.com

न्यू देहली पोस्ट

संपादकीय

भारतीय उपमहाद्वीप की आंतरिक बेबसी

बेबस केवल इंसान ही नहीं होता। बेबसी किसी देश की भी होती है। हर देश की अपनी परेशानी अलग तरह की भी है। भारत की कुछ अलग परेशानी है तो पडोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश की अपनी उलझने हैं। इसी तरह श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान की अपनी ख़ास बेबसी है। परेशानी है और उलझने भी। भारत की ही बात की जाए तो कई समस्या खड़ी दिख रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच की बढ़ती खाई कई दफा लोकतंत्र को भी उलझन में डाल देता है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की अपनी परेशानी है। उसकी परेशानी यह है कि पुरे देश में उसका राज हो। बीजेपी के सिवा कोई नहीं हो। जहाँ भी हो बीजेपी ही हो। यहाँ हिन्दू और मुसलमानो के बीच भी सैद्धांतिक लड़ाई चल रही है। हालांकि बाकी देशों की तरह यहाँ हिन्दू और मुसलमान के बीच सामाजिक तौर पर कोई दुराव नहीं है लेकिन भारत के मुसलमान राजनितिक तौर पर बीजेपी के निशाने पर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत का लोकतंत्र ,भारत का संविधान और भारत के बहुतेरे लोग आज भी मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिलकर इस देश पर मर मिटने को तैयार है। उधर भारत की न्यायपालिका इनदिनों कटघरे में खड़ी दिख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस पर जिस तरह के इल्जाम लग फ़राहे हैं वे भारत की एक अलग सूरत दुनिया में पेश कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के घर से 15 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिलने मकई बात कहि जा रही है। हालाँकि ये नकदी अब जले नोटों के रूप में सामने आ रहे हैं लेकिन न्यायपालिका को तो बदरंग कर ही दिया है। लोगों में न्याय के प्रति अविश्वास बढ़ा है और आम जनता के बीच यह मैसेज जा रहा है कि जब न्याय वयवस्था ही नोटों के बंडल पर जा टिकी हो तो फिर आम जंगता को रहत कौन देगा ?

उधर बांग्ला देश की अपनी बेबसी है। शेख हसीना की सरकार हटने के बाद लगा था कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है और बड़ी बात की अल्पसंख्यक समुदाय आज भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कह सकते हैं बंगलदेश पहले से ज्यादा अशांत हो चला है। अब खबर मिल रही है कि वहां मिलिट्री शासन की व्यवस्था की जा सकती है। मतलब कि वहां एक और तख्तापलट हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना की वापसी भी हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच बांग्लादेश की जनता आज भी रुदाली करती फिर रही है। पाकिस्तान का तो और भी बुरा हाल है। वहां की सरकार की अपनी आंतरिक परेशानी तो है ही अब बलूचिस्तान से जो आग धधक रही है वह पाकिस्तान के लिए परेशानी का कारण बनने जा रहा है। बलूचिस्तान अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ रहने को तैयार नहीं है। संघर्ष और आंदोलन चल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका है लेकिन यहाँ की धरती काफी धनी है। पाकिस्तान को चाहिए कि बलूचिस्तान के लोगों को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा नहीं होता है तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बड़ा नासूर बन सकता है और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान गंभीर संकट में जा सकता है।

'सौगात-ए-मोदी' से क्या बदलेगा मुस्लिम वोटरों का मिज़ाज?

न्यू देहली पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी अपने फैसलों से हमेशा सबको चौंकाते आए हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है! मोदी ने 'सौगात-ए-मोदी' योजना के तहत गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर एक खास किट देने का ऐलान किया है। इस योजना को लेकर अब देशभर में चर्चा तेज हो गई है। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या यह सरकार की गरीबों के लिए सच्ची हमदर्दी है या चुनावी रणनीति का हिस्सा? विपक्षी दलों ने इसे 'राजनीतिक लॉलीपॉप' बताया, तो भाजपा ने इसे 'गरीबों की मदद' करार दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह क्या इस सौगात से भाजपा को मुस्लिम वोटों का फायदा होगा, या फिर यह सिर्फ एक और चुनावी स्टंट साबित होगा ?

दरअसल, भाजपा ने बीते मंगलवार को सौगात-ए-मोदी अभियान की शुरुआत की। इसके तहत देशभर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। मोर्चे के 32 हजार कार्यकर्ता देश की 32 हजार मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ये किट पहुंचाएगी। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। बता दें कि इस योजना की निगरानी खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा रखेंगे। खबर के मुताबिक 'सौगात-ए-मोदी' किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है। इसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता-पायजामा, दाल, चावल, सेवई, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा, खजूर शामिल हैं। प्रत्येक किट की कीमत 500-600 के करीब बताई गई है। बीजेपी का अचानक से जागा ये मुस्लिम प्रेम विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'सौगात-ए-मोदी' योजना, जिसमें ईद के मौके पर गरीब मुस्लिम परिवारों को विशेष किट दिए जाने का ऐलान किया गया है, इस पर देश की विपक्षी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दल इसे 'चुनावी स्टंट', 'नकली हमदर्दी' और 'भाजपा का ढोंग' करार दे रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि "समाजवादियों का हमेशा यह पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए किसी भी धर्म के हो।"

तो वहीं, यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा द्वारा ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे, ईस्टर पर 32 लाख गरीब अल्पसंख्यक परिवारों तक सौगात-ए-मोदी के रूप में पीएम का प्रेम संदेश व भेंट पहुंचाने की घोषणा केवल इनका राजनीतिक स्वार्थ है। उधर ,सौगात-ए- मोदी पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि बीजेपी का यह अभियान दिखावा और छलावा है। उन्होंने भाजपा की तुलना मगरमच्छ से करते हुए कहा कि मगरमच्छ दूर से हंसता है और पास आने पर खा जाता है, यही हाल बीजेपी का है। सौगात ए मोदी पर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कटाक्ष करते हुए कहा, "सौगात शब्द बोलने पर शर्म आनी चाहिए। यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं." उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स पेयर के पैसे से कुछ भी दे रही है, इसे तोहफा या सौगात नहीं कहा जा सकता। वहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस अभियान का स्वागत करते हुए कहा, "यह अच्छी पहल है, लेकिन मुसलमानों को केवल ईद की सौगात नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की सौगात भी चाहिए। पीएम मोदी 'छावा' मूवी देख रहे हैं, दूसरी तरफ ईद की सौगात दे रहे है। अब सवाल उठता है कि क्या सौगाते -ए मोदी वाकई देश की तस्वीर बदलेगा या फिर यह महज एक चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा? जनता क्या सोचती है, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।

ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर सदन में रार

न्यूज़ डेस्क

ओडिशा विधानसभा ने पिछले दिनों अनुशासनहीनता, सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और अध्यक्ष की कुर्सी का उचित सम्मान न करने के आरोप में कांग्रेस के बारह विधायकों को सात दिनों के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। विधानसभा में कांग्रेस के 14 विधायक हैं। पिछले चार दिनों से कांग्रेस ने राज्य विधानसभा के अंदर घंटे-घड़ियाल और शहनाई और बांसुरी बजाकर भाजपा सरकार को राज्य में महिलाओं की दुर्दशा के बारे में जानने का अनोखा तरीका अपनाया है।

निलंबन आदेश के बावजूद, कांग्रेस विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर सदन समिति के गठन की मांग को लेकर सदन में धरना देना जारी रखा। अध्यक्ष ने विधायकों से सदन खाली करने को कहा था। सूत्रों ने कहा कि जब कांग्रेस विधायक नहीं गए तो अध्यक्ष ने सदन के मार्शलों से उन्हें जबरन बाहर निकालने को कहा।महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों की जांच के लिए सदन समिति के गठन की मांग को लेकर कांग्रेस और भाजपा सरकार के बीच पिछले दस दिनों से गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस विधायक दसरथी गोमंगा ने कहा "महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार सदन समिति के गठन की हमारी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है। आदिवासी लड़कियों को छात्रावासों में यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। क्या इन मुद्दों को उठाना अपराध है? ''

बीजद ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। बीजद ने कहा कि "सात दिनों के लिए सदन से बारह विधायकों को निलंबित करना गलत है। हमने पहले देखा था कि भाजपा ने विपक्षी दल के रूप में अपनी भूमिका के दौरान सदन में कैसा प्रदर्शन किया। सरकार कह रही है कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे की जांच के लिए सदन समिति बनाने की कांग्रेस की मांग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं?" अब ज़रा एक नजर ओडिशा में एससी ,एसटी और खासकर इन समुदाय की महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों जानकारी जरुरी है। यह इसलिए कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस और ओडिशा सरकार के बीच टकराव जारी है।

ओडिशा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों का अंत नहीं दिख रहा है। एनसीआरबी की भारत में अपराध-2024 रिपोर्ट बताती है कि एसटी के खिलाफ अत्याचार 2020 में 624 से बढ़कर 2022 में 773 हो गए। ये मामले हत्या, हत्या के प्रयास, महिलाओं की शील भंग करने, बलात्कार और आपराधिक धमकी से संबंधित हैं। एसटी के खिलाफ अपराधों में सजा की दर सिर्फ 19.6 प्रतिशत है। हालांकि, एसटी की तुलना में एससी अत्याचारों के लिए अधिक प्रवण हैं। अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध 2020 में 2,046 से बढ़कर 2022 में 2,902 हो गए। ये अत्याचार हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी और बलात्कार भी हैं। हालांकि मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन दोषसिद्धि दर केवल 16.1 प्रतिशत है।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि ओडिशा उन पांच राज्यों में से एक है, जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 के तहत एससी और एसटी के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए केंद्र से अधिकांश धन प्राप्त होता है। बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य स्तर पर उपर्युक्त दो अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है। इसके तहत, ओडिशा को वर्ष 2024-25 (3 मार्च, 2025 तक) के लिए एसटी और एससी के खिलाफ अत्याचारों को रोकने और पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए 35.81 करोड़ रुपये मिले। जहां तक इन निधियों का सवाल है, ओडिशा पांचवें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश (89.49 करोड़ रुपये), मध्य प्रदेश (88.12 करोड़ रुपये), कर्नाटक (48.66 करोड़ रुपये) और बिहार (46.34 करोड़ रुपये) के बाद यह संख्या बहुत अधिक है। एसटी और एससी विकास विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा सरकार ने पिछले 10 महीनों (पिछले साल जून से अब तक) में एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) नियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 के तहत पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 20.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 2,116 एससी/एसटी अत्याचार पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है।

खबर के मुताबिक़ बलांगीर में सबसे अधिक 202 पीड़ित हैं, जबकि पुरी, जाजपुर, गंजम, ढेंकनाल, कटक और बरगढ़ भी ऐसे अपराधों के केंद्र बने हुए हैं।सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह के मामलों में वृद्धि के पीछे अधिनियम के खराब क्रियान्वयन और राज्य में अत्याचार पीड़ितों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की कमी को जिम्मेदार ठहराते हैं। दलित अधिकार कार्यकर्ता अनिल मलिक ने कहा, "पिछले एक साल में, बिरडी (जगतसिंहपुर) और पिपिली (पुरी) के दो अनुसूचित जाति के युवकों को चोरी के आरोप में उनके गले में चप्पलों की माला पहनाकर और उनके चेहरे पर कालिख पोतकर पूरे गांव में घुमाया गया। बलांगीर में, एक अनुसूचित जनजाति की लड़की को मलमूत्र खाने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन, इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।"

गृह विभाग द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र के अनुसार, वर्ष 2024 में ओडिशा में बलात्कार के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और हत्या के मामलों में कमी आई है। श्वेत पत्र के अनुसार, राज्य ने कैलेंडर वर्ष 2024 में 3,054 बलात्कार के मामले और 1,258 हत्या के मामले दर्ज किए हैं, जबकि 2023 में ओडिशा के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 2,826 बलात्कार और 1,362 हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं।बलात्कार के मामलों में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि हत्या के मामलों में 7.6 प्रतिशत की कमी आई है।वर्ष 2024 के दौरान 1,258 हत्या, 356 डकैती, 2,582 डकैती, 6,408 सेंधमारी, 17,805 चोरी, 6,307 ठगी, 1,471 दंगा, 3,054 बलात्कार, 12,375 मोटर वाहन दुर्घटना और 1,62,497 अन्य विविध मामलों सहित कुल 2,14,113 संज्ञेय मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बलात्कार के 3,054 दर्ज मामलों में से पुलिस ने जांच के दौरान 2,986 मामलों को सही पाया और 1,948 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए। इसी तरह, पिछले साल दर्ज 1,258 हत्या के मामलों में से 1,215 मामले सही पाए गए और 542 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए।

सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया एक लाख करोड़ का बजट

न्यूज़ डेस्क

दिल्ली की बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 25 मार्च को विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। सीएम रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें बिजली, सड़क, पानी और संपर्क सहित 10 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसे ''ऐतिहासिक बजट'' करार दते हुए इस बात पर जोर दिया कि ''भ्रष्टाचार और अक्षमता'' का दौर अब समाप्त हो गया है, क्योंकि सरकार ने पूंजीगत व्यय को दोगुना कर 28,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट परिव्यय पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाल रही सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, ''यह कोई साधारण बजट नहीं है, यह बजट पिछले 10 वर्षों में बर्बाद हुई दिल्ली के विकास की दिशा में पहला कदम है। पिछले एक दशक में दिल्ली विकास के हर पहलू में पिछड़ती चली गई। पिछली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया।'' बजट में मुख्य तौर पर यमुना नदी की सफाई और पुनरुद्धार पर ध्यान दिया गया जो 'साबरमती रिवर फ्रंट' परियोजना से प्रेरित है। सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि 40 'सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट' (एसटीपी) के विकेंद्रीकरण के माध्यम से केवल उपचारित पानी ही नदी में जाए।

इसके अलावा एसटीपी की मरम्मत तथा उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये और पुरानी सीवर लाइन को बदलने के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है तथा संबंधित परियोजनाओं के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,874 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र स्थापित करने और 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' पहल का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर बेहतर परिवहन संपर्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

महिलाओं के कल्याण के मकसद से पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। गुप्ता ने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को निवेश व नवाचार के अनुकूल शहर बनाना है। इसके लिए नई औद्योगिक नीति और नई गोदाम नीति पेश की जाएगी। व्यापारी कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी।

इसके अलावा, दिल्ली में पहली बार वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह हर दो वर्ष में आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए मधुमक्खी पालन सहित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार ने झुग्गी-बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये और पूरे शहर में 100 'अटल कैंटीन' स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया। मुख्यमंत्री ने कहा,''आप सरकार ने 9वीं और 11वीं कक्षा में कई छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया ताकि उनके 10वीं और 12वीं के नतीजे बेहतर दिखें।'' शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार 'पीएम श्री स्कूल' से प्रेरित होकर नई शिक्षा नीति के अनुरूप 'सीएम श्री स्कूल' शुरू करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इन स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार 10वीं कक्षा पास करने वाले 1,200 विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराएगी और इसके लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

कैंसर की चपेट में यूपी महाराष्ट्र और बंगाल समेत पांच राज्य

न्यूज़ डेस्क

देश के पांच राज्यों में कैंसर आफत बनकर सामने आ रही है। अगर समय रहते इन राज्यों में कैंसर के खिलाफ अभियान नहीं चलाये गए तो समस्या अजर भी विकट हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रतापराव जाधव ने संसद के भीतर एक लिखित जवाब में कहा है कि कैंसर के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश ,महाराष्ट्र ,पश्चिम बंगाल ,बिहार और तमिलनाडु में। जाधव ने कहा है कि गैर-संचारी रोगों यानी एनसीडी में वृद्धि को देखते हुए मंत्रालय ने 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की 100% जांच करने के लिए 20 फरवरी से 31 मार्च तक अभियान चलाया है।

मंत्री ने कहा, "यह अभियान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से पूरे देश में चलाया जा रहा है।" भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)-राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि कैंसर के सबसे ज्यादा मामले वाले पांच राज्य उत्तर प्रदेश (2,10,958 मामले), महाराष्ट्र (1,21,717), पश्चिम बंगाल (1,13,581), बिहार (1,09,274) और तमिलनाडु (93,536) हैं। कैंसर मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। जाधव ने कहा कि आईसीएमआर-एनसीआरपी के आंकड़ों के अनुसार, 2025 तक देश में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 15,69,793 है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में कैंसर के मामले 2040 तक बढ़कर 22,18,694 हो जाने की संभावना है।

मंत्री ने कहा कि कैंसर के मामलों में वृद्धि का कारण पता लगाने के लिए बेहतर नैदानिक तकनीकों की पहुंच और उपलब्धता, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, वृद्ध आबादी की बढ़ती हिस्सेदारी, स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य व्यवहार है।इसके अलावा, कैंसर सहित एनसीडी से जुड़े जोखिम कारकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जैसे तंबाकू और शराब का सेवन, अपर्याप्त शारीरिक गतिविधियां, अस्वास्थ्यकर आहार, अधिक नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन। उधर , ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में कैंसर के मामलों की अनुमानित घटना (14,13,316, दर 98.5 प्रति 100000) चीन (48,24,703, दर 201.6 प्रति 100000) और संयुक्त राज्य अमेरिका (23,80,189, दर 367 प्रति 100000) के बाद तीसरे सबसे अधिक कैंसर के मामले हैं। आईसीएमआर-एनसीआरपी के आंकड़ों के अनुसार, देश में पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः फेफड़े और स्तन कैंसर के सबसे आम प्रकार हैं।मंत्री ने कहा कि बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार, सरकार पूरे भारत में जिला अस्पतालों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) स्थापित करने की योजना बना रही है।

क्या पीके की वजह से बिहार इंडिया में पड़ेगी दरार?

अखिलेश अखिल

क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार इंडिया में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है ?क्या मगठबन्धन में दरार पड़ सकती है और क्या राजद और कांग्रेस के बीच तल्खी और बढ़ सकती है ? ऐसे ही कुछ और भी सवाल हैं जो बिहार से दिल्ली तक के सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। यह बात और है कि कांग्रेस ने साफ़ कर दिया है कि आगामी बिहार विधानदसभा चुनाव वह राजद के साथ ही लड़ेगी लेकिन कांग्रेस ने कुछ शर्त भी है। वह शर्त क्या है यह अभी किसी को पता नहीं। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राहुल गाँधी ने फिलहाल राजद नेता तेजस्वी यादव के सीएम उम्मीदवारी को लेकर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। कांग्रेस चाहती है कि चुनावी मैदान में महागठबंधन की सभी पार्टियां पूरी ताकत और सहयोग के साथ उतरेगी और परिणाम आने के बाद सीएम उम्मीदवार का नाम तय होगा। कुछ जानकार यह भी कह फ़राहे हैं कि कांग्रेस यह भी चाहती है कि अगर चुनाव में महागठबंधन की जीत होती है तो सीएम और डिप्टी सीएम कोई नया चेहरा भी हो सकता है। अगर कांग्रेस बेहतर परिणाम लाती है तो सीएम उम्मीदवार कांग्रेस के भी हो सकते हैं और यदि राजद बेहतर परिणाम लाती है तो कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम उम्मीदवार दिया जा सकता है। ये उम्मीदवार दलित भी हो सकते हैं और अल्पसंख्यक भी। लेकिन अब एक नया खेल भी सामने आता दिख रहा है। जान सुराज वाले प्रशांत किशोर की राहुल गांधी से काफी नजदीकियां बढ़ती जा रही है। इन नजदीकियों का चुनाव आते -आते कितना असर पडेगा यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता है लेकिन अभी हाल में ही जिस तरह से जन सूरज पार्ट्री ने पटना छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई को समर्थन देते हुए अपने छात्र इकाई को रद्द कर दिया है उससे भविष्य के संकेत मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि चुनाव आते -आते प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज कांग्रेस के साथ तालमेल कर सकती है और फिर बिहार इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी बन सकती है।

पिछले दिनों बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारु से राहुल और प्रशांत किशोर के बीच मधुर होते सम्बन्ध के बारे में कुसगठ सवाल किये गए थे। पूछा गया था कि क्या जन सूरज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी ? पहले तो कृष्णा अल्लावारु ने इस सवाल को टालने की कोशिश की लेकिन बाद में उन्होंने यह कह दिया कि ''हम इस मसले पर चर्चा करेंगे और पार्टी हाईकमान के फैसले के बाद ही कुछ संभव हो पायेगा। हम किस मसले पर बैठ कर बात करेंगे और अभी समय भी है। '' कृष्णा अल्लावारु के बयान के बाद बहुत कुछ समझ में आने लगी है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने छात्र संघ चुनाव में जन सुराज का समर्थन दिया है यह कोई मामूली बात नहीं हो सकती। इसके कुछ राजनीतिक खेल हो सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की जीत होती है तो बिहार कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है और इसमें जन सुराज के सहयोग को कंगतर नहीं माना जा सकता। ऐसे में इस बात की बड़ी सम्भावना है कि जन सुराज कांग्रेस के नजदीक आ सकती है और फिर दोनों मिलकर बिहार में कोई बड़ा खेल भी कर सकती है। लेकिन यह भी सच है कि अभी कांग्रेस की स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं है कि वह राजद के बिना चुनावी मैदान में चली जाए। ऐसे में कांग्रेस राजद के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी लेकिन वह जनसुराज को अपने पाले में रखकर अपने कोटे से सीट शेयरिंग कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या यह सब राजद अजर उसके नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव को स्वीकार होंगे ?

दरअसल प्रशांत किशोर लगातर नीतीश कुमार दसे लेकर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला करते रहे हैं। बिहार की मौजूदा हालत के लिए पीके इन्ही नेताओं को दोषी मानते रहे हैं। उन्हें लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति नहीं भाती और न ही नीतीश का मॉडल उन्हें अच्छा लगता है। वे तेजस्वी की शिक्षा पर लगातार कटाक्ष करते रहे हैं और राजनीतिक समझ पर भी हमलावर रहे हैं। पीके ने अपने एक बयान में तेजस्वी को लेकर कहा था कि तेजस्वी यादव की कोई अपनी पहचान नहीं है और वे सिर्फ अपने पिता लालू प्रसाद यादव की वजह से राजनीति में हैं। उन्होंने राजद नेता को चुनौती दी थी कि अगर तेजस्वी बिना कागज देखे जीडीपी का फुल फॉर्म और मतलब बता दें, तो वे उनकी बात मान लेंगे। उनका कहना था कि तेजस्वी को विकास जैसे जटिल मुद्दों की समझ नहीं है और उनकी बातें हास्यास्पद हैं।

प्रशांत किशोर लालू यादव पर भी टिप्पणी करते रहे हैं। उन्होंने लालू पर बिहार की जनता को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और कहा कि लालू ने बिहार को गरीबी व पिछड़ेपन में धकेल दिया। ऐसे में एक बड़ी सम्भावना यह है कि लालू यादव पार्टी के साथ कांग्रेस की नजदीकियों के खिलाफ जा सकते हैं और वे प्रशांत किशोर पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। और अगर राजद के भीतर प्रशांत किशोर को लेकर कोई बड़ा मुदा बनता है तो महागठबंधन में दरार भी आ सकती है। हालांकि बिहार के कई नेता यह भी कहते हैं कि राजनीति में आरोप -प्रत्यारोप चलते रहते हैं। पसंद और नापसंद से राजनीति नहीं चलती। राजनीति में सिर्फ लाभ देखा जाता है और अगर प्रशांत किशोर के साथ आने से महागठबंधन में कुछ सीटें और बढ़ सकती है तो राजद उसे मना नहीं कर सकती। जानकार यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी पलटी मारते रहे हैं फिर भी वे दोनों मगठबन्धन में आज भी स्वीकार्य हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर अगर महागठबंधन से जुड़ते हैं तो कांग्रेस को बड़ा लाभ हो सकता है।

क्या चाचा के साथ फिर लौटेगा भतीजा ?

न्यूज़ डेस्क

वैसे राजनीति का कोई चेहरा तो होता नहीं। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है तो राजनीति भी बदल जाती है। एक ही व्यक्ति अलग -अलग समय में क्या कुछ कहता है और क्या कुछ करता है यह देश और समाज को पता है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार चल तो रही है लेकिन भीतर ही भीतर सरकार में शामिल घटक दलों के बीच रोष भी है। शिंदे की अपनी कहानी है तो अजित पवार की अपनी कहानी। ऐसे में अब यह खबर भी सामने आ रही है कि एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी काफी नाराज चल रहे हैं और मौजूदा राजनीति से वे खुश भी नहीं हैं। बीजेपी जिस तरह की राजनीति को आगे बढ़ा रही है ,अजित पवार उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि सत्ता के लालच में अपने चाचा से बगावत करके 'ईडी' सरकार में शामिल होनेवाले अजीत दादा पवार की वापसी की अटकलें लगने लगी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 'दादा' अब अपने चाचा के 'चरणों' में लौट सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार में अपनी उपेक्षा से दादा परेशान हैं। ऐसे में वे अपने कुछ पुराने साथियों से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं।

गौरतलब है कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता। पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक गलियारों में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। ऐसे में अब लोगों की नजरें अजित पवार की ओर लगी हैं। 'ईडी' सरकार में अजित पवार गुट के विधायकों को महत्व नहीं मिलने से उनमें भाजपा नेतृत्व वाली महायुति सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ गई है, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि दादा अपने चाचा के पास वापस लौट सकते हैं। पिछले दिनों इसकी संभावना को तब और बल मिला जब पुणे के एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक बड़े नेता के बीच मुलाकात हुई।

खबर के अनुसार, राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील के साथ दादा की मुलाकात हुई है। पुणे में यह मुलाकात एक बंद कमरे में हुई। दोनों के बीच बंद कमरे में हुई चर्चा के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं।इस बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि वे दोनों एक बैठक के लिए ही एकत्रित हुए थे, लेकिन सूत्रों की मानें तो पवार परिवार के इन दोनों गुटों के बीच की दूरी कम होती हुई नजर आ रही है। भाजपा की फूट डालो राज करो की नीति के तहत महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल-पुथल देखने को मिली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस में फूट पड़ने के बाद अजीत पवार गुट अलग बन गया, लेकिन हाल में हो रही बैठकों, चर्चाओं और कार्यक्रमों में एक मंच पर आने जैसी घटनाओं को देखते हुए दोनों पक्षों के बीच की दूरी कम होती हुई दिखाई दे रही है। भविष्य में ये दोनों पक्ष एक साथ आएंगे, यह भी चर्चा तेज हो गई है। उनके बीच नजदीकियां बढ़ती देख चर्चा सच साबित होने की प्रबल संभावना है।

इस बारे में छगन भुजबल ने कहा कि वे पंचांग मंगवाएंगे और अच्छा मुहूर्त देखेंगे। उन्होंने इस सवाल पर मजाकिया लहजे में कहा कि जलगांव में अच्छे ज्योतिषी हैं, समता परिषद के सम्मेलन में उन्होंने राज्य में शक्ति प्रदर्शन करके मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया है।

पत्रकार -सांसद सागरिका घोष ने क्यों की दागी सुधीर चौधरी पर हमला ?

न्यूज़ डेस्क

जब से यह खबर फैली की पत्रकार सुधीर चौधरी अब सरकारी चैनल दूरदर्शन में एक कार्यक्रम करेंगे और इसके लिए उन्हें हर साल 15 करोड़ से ज्यादा की राशि सरकार देगी ,तभी से सुधीर चौधरी विपक्ष के निशाने पर हैं और पत्रकारिता जगत में भी सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना की जा रही है। लोग यह कह फ़राहे हैं कि आखिर सरकार सुधीर चौधरी को इतनी बड़ी राशि किस काम के लिए दे रही है ? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि आखिर सुधीर चौधरी के जरिये सरकार क्या कुछ करना चाह रही है और फिर जनता के पैसे को सुधीर चौधरी जैसे दागी और भोंपू पत्रकार पर क्यों लुटाया जा रहा है ? क्या सुधीर चौधरी को दी जाने वाली रकम बीजेपी देगी या फिर जनता के पैसे से अपनी छवि का निर्माण और विपक्ष का अपमान कराएगी ? ऐसे बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर किये जा रहे हैं।

सुधीर चौधरी का का मामला अब संसद में भी उठ रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सांसद भी चौधरी के नाम और काम से परेशान रहे हैं और उन्हें भी लग रहा है कि चौधरी जैसे दागी पत्रकार पर सरकार जो खर्च कर रही है वह देश और दूरदर्शन के लिए किसी घात से कम नहीं। सरकार संसद में उठे इस मामले पर आगे क्या कुछ संज्ञान लेती है यह तो बाद का विषय हो सकता है लेकिन सुधीर चौधरी अब एक बड़ी खबर तो बन ही गए हैं।

पत्रकार से तृणमूल की राज्यसभा सदस्य बनीं सागरिका घोष ने पिछले दिनों टीवी की नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री पर निशाना साधा। और रिया चक्रवर्ती के अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा टीवी समाचार का व्यवसाय मॉडल टूट चुका है और यही कारण है कि टेलीविजन समाचार चैनल चरित्र हनन और लोगों को निशाना बनाने में लगे हैं, उन्होंने सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन के समाचार एंकर सुधीर चौधरी के साथ कथित अनुबंध की काफी आलोचना भी की।घोष ने संसद में अपने भाषण में चौधरी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर उनके भाषण का एक वीडियो क्लिप इस लाइन के साथ फिर से पोस्ट कियाः "आज संसद में, मैंने @sudhirchaudhary और नफरत और झूठ की टीवी समाचार फैक्ट्री की आलोचना की।"

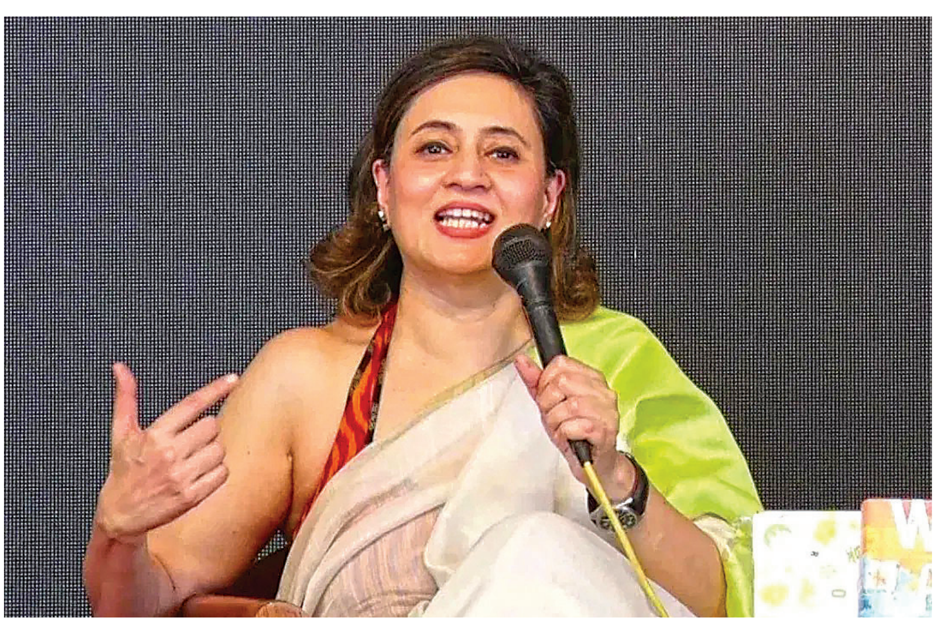

घोष ने साथी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को परेशान करने का मुद्दा उठाया।उन्होंने कहा, "चार साल पहले, न्यूज़ चैनलों ने एक फिल्म अभिनेता के खिलाफ़ एक प्रेरित अभियान चलाया था।

संसद में दूरदर्शन के पुनरुद्धार का आह्वान करते हुए उन्होंने जो कहा ,"नई मीडिया तकनीक दुनिया को छोटा कर रही हैं। विविधता और बहुलवाद में निहित जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत की अनूठी पहचान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक परिसंपत्ति है और इसे वैश्विक मंच पर पेश किए जाने की आवश्यकता है," उन्होंने कहा यह तभी संभव है जब हमारा राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन वास्तव में विश्व स्तरीय बनने की आकांक्षा रखता है। नेटवर्क रूस टुडे तेजी से विस्तार कर रहा है और रूस के संदेश को दुनिया तक पहुंचा रहा है। अल-जजीरा जैसे नेटवर्क दुनिया में अरब की आवाज को पेश करने के लिए सरकारी धन का उपयोग कर रहे हैं।दूरदर्शन यह भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उच्च श्रेणी की, आधुनिक सामग्री और प्रबंधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत को 1990 के प्रसार भारती अधिनियम के अनुसार एक विश्वस्तरीय सार्वजनिक प्रसारक की आवश्यकता है। घोष ने संसद में कहा कि "दुख की बात है कि ऐसी खबरें हैं कि दूरदर्शन ने एक निजी व्यक्ति के साथ एक आकर्षक अनुबंध किया है, जो टेलीविजन पर अत्यधिक विभाजनकारी, भड़काऊ और घृणा फैलाने वाली भाषा का प्रयोग करता है और जो जबरन वसूली के आपराधिक आरोपों में दो बार जेल की सजा काट चुका है।'' उन्होंने कहा कि यह देखना बेहद परेशान करने वाला है कि ऐसे बेहद दागदार रिकॉर्ड वाले व्यक्ति हमारे गौरवशाली राष्ट्रीय प्रसारक का हिस्सा बन सकते हैं।'' सागरिका घोष ने कहा कि ''इंडियन एक्सप्रेस समेत कई प्रकाशनों ने बताया है कि दूरदर्शन मेसर्स ईएसपीआरआईटी प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 15 करोड़ रुपये का अनुबंध कर रहा है, जिसके तहत चौधरी एक दैनिक शो का निर्माण करेंगे, जिसे दूरदर्शन पर सप्ताह के दिनों में प्रसारित किया जाएगा। इस कदम के समर्थक इसे भारत के सार्वजनिक प्रसारक का बहुत जरूरी सुधार बताते हैं। मैं 35 साल से पत्रकार हूँ और आज टेलीविजन न्यूज में जिस तरह से तुच्छ करण, चरित्र हनन और सनसनीखेज का चलन है, उसे देखना दुखद है। आज, लगभग 400 लाइसेंस प्राप्त न्यूज़ चैनल सबसे कम आम भाजक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।''

घोष ने साथी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को परेशान करने का मुद्दा उठाया।उन्होंने कहा, "चार साल पहले, न्यूज़ चैनलों ने एक फ़िल्म अभिनेता के खिलाफ़ एक प्रेरित अभियान चलाया था। आज वह फ़िल्म अभिनेता निर्दोष साबित हुआ है। उन सभी आरोपों को निराधार बताया गया है। लेकिन मिस रिया चक्रवर्ती को उन वर्षों के अपमान का बदला कौन देगा, जो उन्होंने मीडिया के हाथों झेले हैं?

सवाल यह उठता है कि न्यूज़ मीडिया चैनलों को और अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह कैसे बनाया जा सकता है? मीडिया मालिकों को क्या जल्द ही संसद के पटल पर बुलाया जाएगा।" "दुष्ट एंकर पत्रकारिता के लिए एक कलंक हैं। हम जानते हैं कि टीवी न्यूज़ का बिज़नेस मॉडल टूट चुका है। तो क्या यह मुनाफ़ा कमाने, झूठ और और भी झूठ और फर्जीवाड़े फैलाने का नया तरीका है?" घोष ने कहा कि ''मुझे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी में सेवा करने का सौभाग्य मिला था, जिसके अध्यक्ष प्रतिष्ठित न्यायविद, दिवंगत न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा थे। न्यायमूर्ति वर्मा कहते थे कि मीडिया को स्वतंत्र और जिम्मेदार होना चाहिए, गैर-जिम्मेदार और सेंसर नहीं होना चाहिए। एनबीएसए के पास न तो ताकत थी और न ही कोई वैधानिक शक्ति। हालांकि, आज एक स्वतंत्र मीडिया उद्योग निकाय की तत्काल आवश्यकता है जो पेशेवर प्रसारण और पत्रकारिता निष्पक्षता के वैश्विक मानकों को बनाए रखे।"

भारतीय चुनाव में पैसे का अद्भुत तमाशा

राजनीतिक डेस्क

भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव व्यय का पूरा खुलासा अनिवार्य करने के बावजूद, 'वास्तविक आंकड़ों' पर अभी भी गोपनीयता का पर्दा पड़ा हुआ है। जबकि कुछ दलों ने इसका पालन किया है, लेकिन पूरा वित्तीय सच जनता की नजर से छिपा हुआ है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव यानी सीएचआरआई द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने इस बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि कैसे राजनीतिक दलों ने सत्ता की लड़ाई में अपने चुनावी युद्ध कोष को इकट्ठा किया और खर्च किया।

चुनाव खर्च के लिए सिर्फ़ 22 राजनीतिक दलों के पास 18,742.31 करोड़ रुपये थे, लेकिन राजनीतिक युद्ध के खेल में 3,861.57 करोड़ रुपये उड़ा दिए गए। अकेले चुनावी दान से ही 7,416.31 करोड़ रुपये जुटाए गए, जिसमें से बीजेपी को कुल राशि का 84.5% हिस्सा मिला।बीजेपी ने सबसे ज्यादा 1,737.68 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की जो

कुल खर्च की गई राशि का 45% से ज्यादा था।

सीएचआरआई के निदेशक वेंकटेश नायक ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि यहां धनबल महत्वपूर्ण है और मीडिया ने जो भूमिका निभाई है, उसे देखें तो प्रिंट, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करते हुए मीडिया विज्ञापनों पर 992.48 करोड़ रुपये खर्च किए गए, 196.23 करोड़ रुपये सोशल मीडिया और वर्चुअल अभियानों के लिए समर्पित थे, जिसमें से केवल सात दलों ने ऐसे खर्चों का खुलासा किया। 830.15 करोड़ रुपये 'स्टार प्रचारकों' की असाधारण यात्राओं पर खर्च किए गए। 398.49 करोड़ रुपये हर गली और घर में आकर्षक बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और प्रचार सामग्री पर खर्च किए गए।"

धन के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। चुनाव के अंत में, पार्टी के खजाने में 14,848.46 करोड़ रुपये की भारी राशि बची थी। यह अतिरिक्त धन कहां जाएगा? भाजपा सहित छह राजनीतिक दलों के पास शुरू में जितना पैसा था, उससे कहीं अधिक पैसा आ गया! यह कैसे हुआ? कई प्रमुख दलों- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल- ने अपने व्यय का खुलासा तक नहीं किया है।"

उन्होंने पूछा, "ऐसे खगोलीय आंकड़ों के साथ, एक बात तो स्पष्ट है- भारत में चुनाव अब सिर्फ़ लोकतंत्र के बारे में नहीं रह गए हैं। वे एक उच्च-दांव वित्तीय युद्ध का मैदान बन गए हैं। जब राजनेता अपने करोड़ों के अभियान में मजे ले रहे हैं, तो आम मतदाता सोच रहा है कि इतना सारा पैसा कहां से आता है, और आखिर में इसका फायदा किसे मिलता है?"

इस बड़े-वित्तीय नाटक के पीछे की सच्चाई अभी भी अस्पष्ट है। लेकिन एक बात तो तय है- सिर्फ़ वोट नहीं, बल्कि पैसा भारत के राजनीतिक भाग्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाता है। क्या चुनाव आयोग गैर-अनुपालन पर नकेल कसेगा, या फिर पैसे की ताकत और गोपनीयता का यह चक्र बेरोकटोक जारी रहेगा?

और फिर दूसरे नजरिये से देखा जाए तो चुनावी अभियान में बीजेपी के सामने कोई भी पार्टी टिक नहीं पा रही है। क्षेत्रीय पार्टियों को कौन कहे ,कांग्रेस उसके सामने कहीं भी टिक नहीं पा रही है। अभी हाल में ही कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट सामने आयी है जिसमे पिछले लोकसभा चुनाव के साथ चार विधानसभा चुनाव में हुए 22 दलों के चुनावी अभियान पर हुए खर्च का ब्योरा दिया गया है। इस आंकड़े से पता चलता है कि बीजेपी समेत 22 दलों ने चुनावी अभियान पर कुल खर्चा 3861.57 करोड़ किये हैं जिनमे सर बीजेपी का ही खर्च 45 फीसदी से ज्यादा है।

इसलिए कोलकाता से असम शिफ्ट हो गया आईपीएल मैच

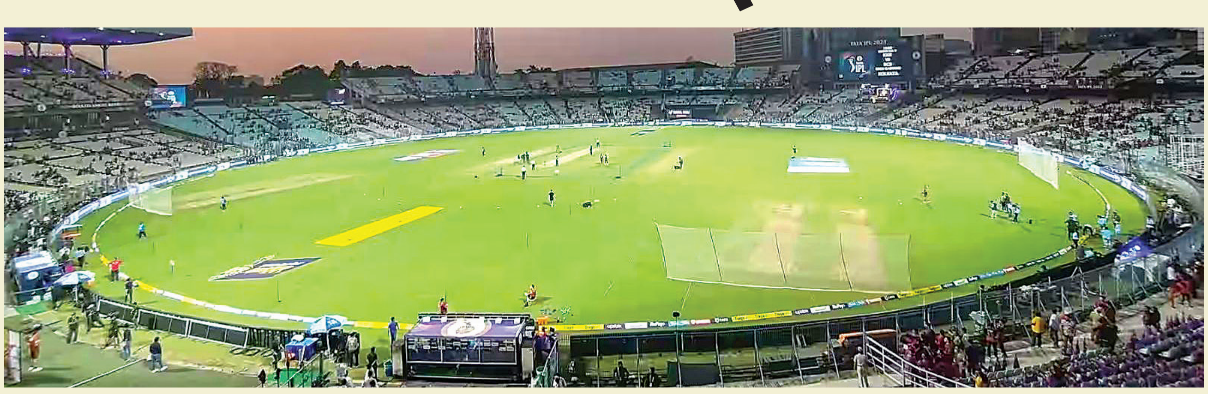

राजनीतिक डेस्क

पश्चिम बंगाल में फिर तांडव की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अगले साल बिहार के बाद बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी हर हाल में ममता की सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है। मजे की बात तो यह है कि 6 अप्रैल को रामनवमी है और इसी दिन कोलकाता में आईपीएल का मैच होना था। बीजेपी इस दिन बड़े पैमाने पर बंगाल में रामनवमी की तैयारी कर रही है। यह तैयारी हिन्दू सेंटीमेंट को जगाने की है ताकि आगामी चुनाव में उसका लाभ मिल सके। उधर टीएमसी भी अपनी तैयारी कर रही है और वह किसी भी सूरत में बीजेपी के हाथ परास्त होना नहीं चाहती। जाहिर है दोनों दलों के बीच इस बार तनातनी होगी ,संभव है कि संघर्ष भी हो और हिंसक घटनाएं भी हो। ममता की सरकार कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटे इसको लेकर काफी अलर्ट है।

6 अप्रैल को रामनवमी है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल में जुलूस निकालेगी और हिंदुओं को एकजुट करेगी। आरोप लगाया जा रहा है कि शासन और प्रशासन रामनवमी की शोभायात्रा में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन ने रामनवमी के दिन कोलकाता में होने वाले आईपीएल मैच के लिए सिक्योरिटी से देने से मना कर दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स से रामनवमी के दिन 6 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच होना था। इस मैच में 65,000 दर्शकों के शामिल होने की संभावना थी। ऐसे में एक तरफ रामनवमी शोभायात्रा और दूसरी तरफ मैच की भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी, इसलिए पश्चिम बंगाल की पुलिस ने आईपीएल मैच के लिए सुरक्षा देने से मना कर दिया। यही वजह है कि केकेआर और एलएसजी के बीच कोलकाता के बजाए गुवाहाटी में मैच होगा। पिछले साल भी रामनवमी के कारण कोलकाता का मैच शिफ्ट हो गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर बीजेपी-टीएमसी के बीच राजनीतिक तकरार देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने अभी से ही रामनवमी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के सीनियर लीडर सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि इस बार राज्यभर में रामनवमी के दिन 6 अप्रैल को 2000 जुलूस निकालेंगे, जिसमें एक करोड़ हिंदू हिस्सा लेंगे। शोभायात्रा निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। भगवान श्रीराम की पूजा करने के लिए अनुमति नहीं लेंगे? हिंदू भाई शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालेंगे। ये प्रशासन को सुनिश्चित करना है कि जुलूस के दौरान दूसरे लोग शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि पिछले साल 1000 रामनवमी की शोभायात्राएं निकाली गई थीं, जिसमें 50 हजार हिंदुओं ने भाग लिया था। उधर ,पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी पार्टी और सरकार एकता पर विश्वास करती है, हर धर्म का सम्मान करती है। इस वक्त रमजान का महीने चल रहा है। हम ईद को शांति से मनाएंगे और रामनवमी को भी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछले साल रामनवमी के दिन हिंसक झड़प हुई थी। मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान उपद्रवियों ने भक्तों पर हमला किया था। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले दागे थे। इसे लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा था।

बंगाल में दीदी को हराने की बड़ी तैयारी

न्यूज़ डेस्क

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी भी चल रही है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी पटखनी देने के बाद अब ममता बनर्जी अगले साल के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी को आउट करने की तैयारी कर रही है। उधर बीजेपी किसी भी सूरत में बंगाल से टीएमसी की राजनीति को समेटने को तैयार है। बीजेपी की चाह है कि वहां डबल इंजन की सरकार हो ताकि बंगाली समाज को सनातनमय किया जाए। याद रहे बंगाल की राजनीति हमेशा से ही सौहार्दपूर्ण रही है और हिन्दू -मुसलमान मिलकर समाज का निर्माण करते रहे हैं। टीएमसी के साथ बंगाल का मुस्लिम समाज है और इसका लाभ भी टीएमसी उठाती रही है। अब बीजेपी किसी भी तरह से हिन्दू समाज को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है ताकि ममता को कमजोर किया जा सके।

भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने पिछले दिनों हल्दिया में "सनातनी एकजुटता" रैली में सांप्रदायिक रंग से सराबोर भाषण में कट्टर हिंदुत्व की नीति को आगे बढ़ाया। 2026 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के एकमात्र उद्देश्य से हिंदुओं से एकजुट होने का आग्रह करते हुए, अधिकारी ने ऐसी भाषा में बात की, जिसे लेकर उनकी पार्टी, भाजपा के एक वर्ग को भी बंगाल जैसे बहुलवादी, समावेशी राज्य में अनिश्चितता है।

अधिकारी ने कहाः "अगर पांच प्रतिशत और हिंदू वोट भाजपा को मिलते हैं, तो हम जीतेंगे।" उन्होंने कहा, "हम बंगाल को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देंगे," उन्होंने सुझाव दिया कि ममता के सत्ता में आने पर ऐसा हो सकता है। "मैं अपने धर्म को बचाने के लिए शहीद होने के लिए तैयार हूं।" बता दें कि कुछ सौ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्वी मिदनापुर टाउनशिप में 2 किलोमीटर की रैली में भाग लिया, जो पार्टी के हल्दिया विधायक तापसी मंडल द्वारा हाल ही में ममता की पार्टी में शामिल होने के जवाब में एक उपाय के रूप में था। उन्होंने कहा कि वे अधिकारी के ध्रुवीकरण के प्रयास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।

अधिकारी द्वारा मुसलमानों के खिलाफ़ की गई मौखिक कटुता से उन्हें असहजता महसूस होती है, जो इस राज्य की आबादी का एक तिहाई हिस्सा है। बता दें कि राज्य की 294 सीटों में से लगभग 120 सीटों के चुनावी नतीजे अल्पसंख्यक तय करते हैं।

अधिकारी ने कहा, "ये रैलियां सभी हिंदुओं के एकीकरण की घोषणा करती हैं, जो अगले साल उनके मुस्लिम लीग शासन (तृणमूल कांग्रेस का जिक्र करते हुए) के अपरिहार्य पतन का कारण बनेगी। ममता बनर्जी का मुस्लिम-तुष्टिकरण और पूरे बंगाल में जिहादियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार की अनुमति देना हिंदुओं के एकजुट होते ही उन्हें पतन की ओर ले जाएगा।"

बता सदन कि दिसंबर 2020 तक तृणमूल के साथ रहने तक दो दशकों से अधिक समय तक धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी रहे अधिकारी, जो अब बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, भाजपा में शामिल होने के बाद से तेजी से सांप्रदायिक होते दिख रहे हैं। सच तो यह है कि अधिकारी अब समाज को बांटने का ही काम करते हैं और उस काम को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। हालांकि बंगाल का समाज अधिकारी के खेल को समझ रहा है लेकिन यह भी सच है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बीजेपी करती रही है वही काम बंगाल में अधिकारी करते दिख रहे हैं। बता दें कि जब बांग्लादेश में उथल-पुथल तेज हुई, तो अधिकारी को लगा कि ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए यह एक मौका है। उन्होंने बार-बार दावा किया है कि वे बंगाल के सभी हिंदुओं की प्रमुख आवाज हैं, जो उनकी पार्टी के कुछ लोगों को पसंद नहीं आया।बीजेपी नेतृत्व में उनकी विभाजित बंगाल इकाई के कई गुटों ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि अधिकारी द्वारा मुसलमानों के खिलाफ़ की गई मौखिक कटुता से उन्हें असहजता महसूस होती है, जो इस राज्य की आबादी का एक तिहाई हिस्सा है। बता दें कि राज्य की 294 सीटों में से लगभग 120 सीटों के चुनावी नतीजे अल्पसंख्यक तय करते हैं।

धनधारी सांसदों की फिर बढ़ गई सैलरी

राजनीतिक डेस्क

संसद में वैसे भी काम की कोई बात होती तो नहीं है लेकिन वहां सत्र के दौरान लगता है कि संसद में कुछ हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है इसकी असली जानकारी अब देश की जनता रखना तक नहीं चाहती। जनता भी जान गई है कि उसे कौरा के रूप में भोजन और कुछ पैसे मिल ही जाते हैं तो फिर सांसद क्या करते हैं और क्या पाते और खाते हैं उस पर चर्चा क्यों की जाए ? जनता यह भी जानती है कि दलीय राजनीति में कोई भी पार्टी एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं है। सत्ता पक्ष का पाना अजेंडा है और विपक्ष का अपना खेल। इस खेल में संसद जो सबसे बड़ा पंचायत कहलाती है उसमे जनता के लिए कुछ बचा नहीं है। हिन्दू -मुसलमान की बात होती है और लगे हाथ देश कितना आगे बढ़ रहा है इसके आंकड़े पेश किये जाते हैं। लेकिन इस देश की हर जनता पर कितना कर्ज चढ़ा हुआ है ,कितने लोग बेरोजगारी से परेशान है हैं और कितने लोग घर छोड़कर दूसरी जगह मजदूरी करने को विवश हैं अजर क्यों विवश हैं इस पर चर्चा नहीं होती। किसान मर रहे हैं ,महाराष्ट्र में हर दिन दर्जन भर किसान जान गवां रहे हैं। और यह सब वर्षो से जारी है लेकिन संसद में आज तक इसका कोई समाधान नहीं निकला।

अब इसी बीच खबर आयी है कि सांसदों के वेतन भत्ते अचानक बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही पूर्व सांसदों के पेंशन में भी बढ़ोत्तरी हुई है। सबसे खास बात है कि यह बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी रहेगी। वेतन और भत्तों में इजाफा के बाद सांसदों को अब 1,24,000 रुपये मिलेंगे। इससे पहले सांसदों को 1 लाख रुपये मिलते थे।अब सांसदों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर दो हजार से ढाई हजार कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन को 25 हजार से बढ़ाकर 31 हजार कर दिया गया है। बता दें कि ये बढ़ोत्तरी सांसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है।

संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया कि पांच साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। संसद के चल रहे बजट सत्र के बीच सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई है।

मौजूदा और पूर्व सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते में पहले का संशोधन अप्रैल 2018 में घोषित किया गया था। 2018 में संशोधन में एक सांसद के लिए घोषित आधार वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह था। इस राशि को निर्धारित करने का उद्देश्य उनके वेतन को मुद्रास्फीति की दरों और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप लाना था। वहीं, 2018 के संशोधन के अनुसार, सांसदों को अपने कार्यालयों को अद्यतन रखने और अपने संबंधित जिलों में मतदाताओं के साथ बातचीत करने की लागत का भुगतान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये का भत्ता मिलता है।

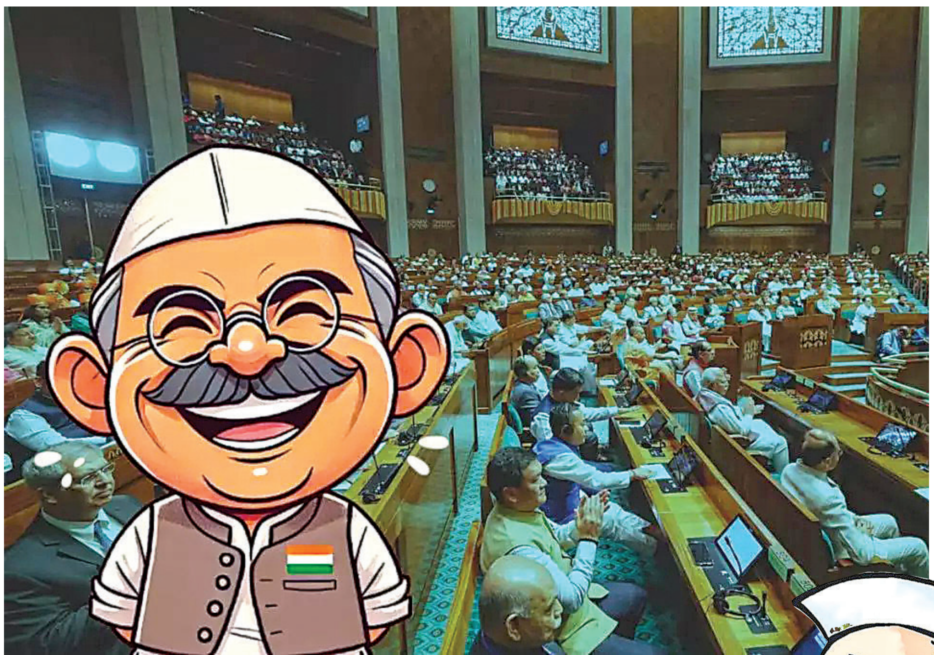

मजे की बात तो यह है कि मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब लड़ाई होती दिखती है लेकिन जब इनके पैसे बढ़ाने की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। कोई इसका विरोध नहीं करता। कह सकते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई को सब मिलजुल कर खाते हैं और फिर जनता के सामने खुद को बड़ा आदमी साबित करते हैं।

जानकारी दें कि सांसदों को कार्यालय भत्ता के रूप में 60,000 रुपये प्रतिमाह और संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोत्तरी की जानी है। इसके अलावा सांसदों को फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए सालाना भत्ता भी मिलता है। सांसद अपने और परिवार के साथ साल भर में कुल 34 फ्री उड़ान भर सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी समय प्रथम श्रेणी की ट्रेन यात्रा कर सकते हैं।

इतना ही नहीं सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी का लाभ भी मिलता है। सरकार उनके आवास और ठहरने की व्यवस्था भी करती है।अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान सांसदों को नई दिल्ली में किराए-मुक्त आवास प्रदान किया जाता है। उन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर छात्रावास के कमरे, अपार्टमेंट या बंगले मिल सकते हैं। जो व्यक्ति आधिकारिक आवास का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, वे मासिक आवास भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं।

अब इतनी सुविधाएं पाने के बाद आखिर इस देश का कौन आदमी नहीं चाहेगा कि बिना काम का लाखों का रोजगार मिल जाए। ऊपर से कमाई अलग से। याद रहे नेता लोग कई तरह से लाभ उठाते हैं। मजे की बात तो यह है कि मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब लड़ाई होती दिखती है लेकिन जब इनके पैसे बढ़ाने की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। कोई इसका विरोध नहीं करता। कह सकते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई को सब मिलजुल कर खाते हैं और फिर जनता के सामने खुद को बड़ा आदमी साबित करते हैं।

क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र बिहार से कर्नाटक भेजने की तैयारी, बिहारी नेता मौन

न्यूज़ डेस्क

पप्पू यादव सांसद तो हैं पूर्णिया से लेकिन पिछले दिनों बेगूसराय में पदयात्रा करते दिखे। उनकी इस यात्रा में काफी भीड़ थी। बड़ी संख्या में युवा तो थे ही बुजुर्ग भी थे और सबसे ज्यादा किसानो का जत्था था। नारा लग रहा था कि बिहार से सौतेला व्यवहार नहीं होने देंगे और क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान को बिहार से कर्नाटक नहीं जाने देंगे। इस नारे के बाद ही पता चला कि माजरा क्या है ? दरअसल केंद्र सरकार बेगूसराय जिले के कुसमहौत स्थित क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक के शिवमोगा भेजना चाहती है और इसकी तैयारी भी कर ली गई। जाहिर है इसके पीछे केंद्र सरकार का अपना तर्क हो सकता है और कुछ मजबूरियां भी हो सकती है। लेकिन यह समझ से परे है कि जब बिहार खुद भी एक कृषि प्रधान राज्य है अजर यहाँ सबसे ज्यादा मक्के की खेती भी होती है तो फिर अनुसंधान केंद्र को बाहर भेजने के पीछे की क्या राजनीति हो सकती है ?

आगे क्या होगा और केंद्र सरकार क्या कुछ करती है इसे देखना होगा लेकिन अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इस मामले को लेकर मुखर हो गए हैं। वे अब इसे बिहार के लिए बड़ा मुद्दा बनाने को तैयार है और जाहिर सी बात है कि अगर बिहार के लोग और खासकर बेगूसराय के लोग और किसान इस मसले को लेकर सरकार के खिलाफ जाते हैं तो मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। ताज्जुब की बात तो यह है

कि उसी बेगूसराय से सांसद हैं लेकिन इस मसले पर मौन है। उधर बिहार सरकार भी चुप्पी साढ़े हुए है। बिहार के बाकी सांसद भी मौन धारण किये हुए हैं। बिहार में तो वैसे भी कोई उद्योग धंधा और शोध संस्थान नहीं है। लेकिन न तो बिहार ससरकार को कोई चिंता है और नहीं बिहार के किसी नेता को ही। भला बीजेपी वाले क्यों बोलेंगे ? चिराग पासवान को क्या मतलब है ?

पप्पू यादव की पदयात्रा बेगूसराय के पावर हाउस चौक से शुरू होकर हड़ताली चौक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों, स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पदयात्रा के दौरान सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र बिहार के किसानों के लिए जीवन रेखा है। इसे कर्नाटक स्थानांतरित करना बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों के हितों पर सीधा हमला है। मक्का उत्पादन में बिहार का अहम योगदान है, फिर भी केंद्र सरकार इस केंद्र को राज्य से बाहर ले जाकर हमारे किसानों को ठगने का काम कर रही है।" उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि बिहार की मिट्टी और किसानों के सम्मान की लड़ाई है। हम चुप नहीं बैठेंगे और इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। केंद्र सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा, वरना बिहार की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।पदयात्रा में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मक्का अनुसंधान केंद्र को बेगूसराय में ही बनाए रखने की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने सरकार से मांग की है कि किसानों की आजीविका से जुड़े इस महत्वपूर्ण संस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय तत्काल रद्द किया जाए।

उन्होंने कहा कि जिले के किसानों की थर्मल पावर को दी गई जमीन की समस्या को लेकर भूमि राजस्व मंत्री संजय सरावगी से बात की है। खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों के खेतों से मिट्टी काटे जाने की समस्या को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी बात की। दोनों ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है।

पप्पू यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इनके जैसे 100 मंत्री भी आ जाएंगे, तब भी यहां से क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केंद्र, कुशमहौत को यहां से स्थानांतरित नहीं होने देंगे। वहीं, स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदू-मुसलमान करना है। जिले के विकास के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है।

बिहार एनडीए को जीतनराम मांझी ने बढ़ाई टेंशन

न्यूज़ डेस्क

बिहार चुनाव के अभी कई महीने बाकी हैं लेकिन एनडीए के भीतर रार मच गई है। सीट को लेकर घटक दलों में बीजेपी पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। यह बात और है कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के भीतर अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है और न ही कोई आधिकारिक चर्चा ही है लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है और एनडीए के को टेंशन हो गया है। अब तो कई लोग यह भी कह रहे हैं कि राजनीतिक नजाकत को देखते हुए मांझी फिर से सीएम की कुर्सी पर नजर लगा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके मन के मुताबिक अगर सीट मिल गई और उसमे से15 से से बीस सीटों पर भी जीत हो गई तो वे खेल करने लायक हो सकते हैं। वे सीएम भी बन सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने गया के शेरघाटी में एक बयान देकर एनडीए के बीच टेंशन बढ़ा दी है। आगामी विधानसभा चुनाव में मांझी ने 40 सीटों की मांग कर दी है। उन्होंने गया की शेरघाटी सीट पर भी दावा ठोका है। साथ ही यहां तक कहा कि शेरघाटी को जिला भी बनाएंगे। राजनीतिक जानकारों की मानें तो जीतन राम मांझी के बयान के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि वो अभी से एनडीए में प्रेशर बनाने के मूड में दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि एनडीए में मांझी की इस मांग का कितना असर होता है।कई राजनेता भी मानते हैं कि चुनाव और सीटों के बंटवारे में अभी वक्त लगेगा, लेकिन दावे ठोके जाने लगे हैं। शेरघाटी अनुमंडल के

रंगलाल हाई स्कूल मैदान में 'हम' पार्टी की ओर 'गरीब चेतना सम्मेलन' का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में काफी भीड़ जुटी थी और भीड़ से यह आवाज भी आ रही थी कि सीएम मांझी को बनाया जाए।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने मंच से कहा कि पूरे बिहार में एनडीए के घटक के रूप में उनकी पार्टी को 40 सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि इसमें से 20 सीट भी हमारी पार्टी को जिताइएगा तो बिहार का अगला सीएम हमारी ही पार्टी का होगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की नजर हम पर है। 'गरीब चेतना सम्मेलन' के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कुछ वादे भी किए। उन्होंने कहा कि वे शेरघाटी में अपने पिछले सीएम कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को फिर से लागू करेंगे। यहां तक कहा कि शेरघाटी को जिला भी बनाएंगे।

क्या बिहारी मुसलमान अब नीतीश का साथ छोड़ देंगे?

राजनीतिक डेस्क

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में बिहारी मुसलमान नहीं पहुंचे। कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नीतीश कुमार को साथ देने से मना कर दिया और यह भी कहा कि चुनाव के दौरान इसका हिसाब लिया जाएगा। बता दें कि जमीयत ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। उधर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया बड़ी संख्या में मुस्लिमो के पहुँचने की बात हुई। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

बिहार की सियासत में मुस्लिमों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17 प्रतिशत के करीब है। मुस्लिम परंपरागत तौर पर पहले कांग्रेस इसके बाद आरजेडी और जेडीयू को वोट करते रहे हैं। बिहार में आरजेडी का एमवाई समीकरण मुस्लिम और यादव वोटर्स पर ही टिका है। 80 के बाद जब लालू यादव पहली बार सत्ता में आए तो उस समय सभी मुस्लिम एकतरफा लालू यादव को वोट करते थे, ऐसे में अब हालात बदल गए हैं। 2005 में जब नीतीश सत्ता में आए तो उन्होंने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की। नतीजा लालू यादव चुनाव हार गए। बिहार में नीतीश कुमार की छवि सेक्युलर नेता की मानी जाती है। उन्हें सर्वधर्म समभाव वाला नेता माना जाता है। उन्होंने तिलक और टोपी की राजनीति साथ-साथ की। हालांकि जब बिहार में बीजेपी का उदय हुआ तो समय-समय पर उनके सेक्युलर नहीं होने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अब जब मुस्लिम संगठनों से इफ्तार पार्टी का विरोध किया है तो क्या इससे नीतीश कुमार को झटका लगेगा?

मुस्लिम संगठनों के विरोध का चुनाव में क्या असर होगा? मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपना फैसला बदल दें। वे सरकार को इस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सपोर्ट नहीं करें। शुरुआत में नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई थी। जिसमें सभी संगठन शामिल हुए। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर कोई बैठक नहीं की। ऐसे में मुस्लिम संगठन इससे नाराज थे। इसको लेकर 26 मार्च को पटना में मुस्लिम संगठनों ने विशाल प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। वहीं आरजेडी और लालू यादव इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं। लालू यादव को शुरुआत से ही मुस्लिमों का समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों की अपील और नीतीश कुमार की आलोचना को आरजेडी ने अपनी सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया। ताकि चुनाव में आरजेडी को मुस्लिम वोट मिल सके। इस पूरे मामले पर बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां ने कहा कि ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है, ये सभी लोग जल्द ही बेनकाब हो जाएंगे।

अब झारखंड सरकार कराएगी जातीय सर्वेक्षण

न्यूज़ डेस्क

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य में अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण कराएगी। राज्य के राजस्व, भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने विधानसभा में इस संबंध में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में जानकारी दी। जातीय जनगणना के सवाल पर मंत्री ने कहा कि राज्य की सरकार जातीय सर्वे कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जातीय सर्वेक्षण कैसे कराया जाए, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य के कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग को सौंपी गई है।

झारखंड विधानसभा के चालू बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान प्रदीप यादव ने सवाल उठाया कि 12 फरवरी 2024 को कैबिनेट की बैठक में जातीय सर्वे कराने को लेकर निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के बाद एक साल एक माह का वक्त बीत गया है, ऐसे में सरकार बताए कि अभी तक इस पर क्या काम हुआ? उन्होंने यह भी जोड़ा कि तेलंगाना जैसे राज्य ने हमसे बाद में जातीय सर्वे कराने का फैसला लिया और वहां फरवरी में इसकी रिपोर्ट भी आ गई है। कांग्रेस नेता के सवाल पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जातीय जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार जातीय सर्वे का काम शुरू कराएगी। इसके लिए किस एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, यह तय करने की प्रक्रिया चल रही है। बाद में सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जातीय गणना सिर्फ जनगणना नहीं, बल्कि समाज का एक्सरे और एमआरआई की रिपोर्ट की तरह है। इससे सिर्फ जातियों की संख्या का पता नहीं चलता, बल्कि यह तस्वीर भी सामने आ जाती है कि कौन सी जातियां और कौन लोग समाज में किस पायदान पर खड़े हैं। प्रदीप यादव ने कहा कि इससे दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के विकास की दिशा में कारगर कदम उठाने में मदद मिलती है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले अपने चुनावी घोषणापत्रों में भी राज्य में जातीय जनगणना कराने का वादा किया था। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य कैबिनेट ने भी इस आशय का निर्णय पारित किया था।

न्यू देहली पोस्ट

आखिर करणी सेना ने सपा सांसद पर हमला क्यों किया?

राजनीतिक डेस्क

हिंदूवादी करणी सेना ने राणा सांगा के बारे में विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया है। यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में मौजूद थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए मामले में आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर निशाना साधा। रामजी लाल सुमन के बेटे रणजीत ने आरोप लगाया कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हरिपर्वत चौराहे के पास स्थित उनके घर में घुसकर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि लाठी-डंडे और तलवार लिए हमलावरों ने परिसर में खड़ी कारों में भी तोड़फोड़ की। अखिलेश यादव ने कहा, ''इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती। बीजेपी सरकार को अपनी भेदभाव वाली आदत को सुधार कर जनता के रोजी-रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कुछ ध्यान देना चाहिए।''

बता दें कि इस घटना के एक वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी उत्पात मचा रही भीड़ से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है। रणजीत ने कहा, ''सोशल मीडिया पर कई दिनों से मेरे पिता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। दो दिन से यह धमकी दी जा रही थी कि आवास का घेराव किया जाएगा। और ऐसा हो भी गया। रणजीत ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि धमकी देने वालों को संरक्षण दिया। घटना पर अभी पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

बता दें कि हाल में सुमन का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्हें कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि राणा सांगा 'गद्दार' थे, जिन्होंने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। राणा सांगा 1508 से 1528 तक मेवाड़ के शासक थे। यादव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आगरा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी के बावजूद, पीडीए (पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग) के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है, तो फिर 'जीरो टॉलरेंस' तो जीरो होना ही है।'' आदित्यनाथ को 'आउटगोइंग सीएम' बताते हुए सपा प्रमुख ने पोस्ट में कहा, ''क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव दिन पर दिन घट रहा है या फिर 'आउटगोइंग सीएम' की अब कोई सुन नहीं रहा है? अगर वह अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से पहचानकर दंडित करें, नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ़ ये सब उनकी अनुमति से हुआ है। निंदनीय!''

यादव ने इससे पहले एक अन्य पोस्ट में कहा, ''सपा सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमज़ोर से कमज़ोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। सपा मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही।'' उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कहा, ''बीजेपी ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक-जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गये इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है।'' उन्होंने कहा, ''हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। आज के समय में बीते कल की, मतलब 'इतिहास' की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। राज काज के निर्णय अपने समय की परिस्थितियों की मांग के हिसाब से लिए जाते थे।''

सपा प्रमुख ने पोस्ट में कहा, ''इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती। बीजेपी सरकार को अपनी भेदभाव वाली आदत को सुधार कर जनता के रोजी-रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कुछ ध्यान देना चाहिए। बीजेपी दरारवादी पार्टी है।'

गुर्जर विधायक से बढ़ रही सीएम योगी की मुश्किलें

न्यूज़ डेस्क

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की सरकार को घेरने वाले भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश पर उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कारण बताओ नोटिस में नंदकिशोर गुर्जर से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है, कि पिछले कुछ समय से आपके द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सरकार की आलोचना की जा रही है एवं आपके वक्तव्यों व कृत्यों से पार्टी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंच रहा है। जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि इस पत्र प्राप्ति के 7 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण दें, कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाए। इस नोटिस के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में छिड़ा घमासान सतह पर आ गया। याद रहे अभी कुछ दिन पहले ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद के खचाखच भरे गुर्जर सम्मेलन में हजारों लोगों के सामने लोनी विधायक जिस नंदकिशोर गुर्जर को इंसाफ दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब उसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

केशव मौर्य ने लोनी के गुर्जर सम्मेलन में कहा कि यह योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसमें राम भक्तों, शिव भक्तों, कृष्ण भक्तों पर लाठी-गोली नहीं बरसायी जाती, बल्कि पुष्प वर्षा की जाती है। आप सभी का शिर ऊंचा रखने के लिये मैं अपने स्तर से कोई कमी नहीं रखूंगा।

बता दें कि योगी पार्ट वन ने विधानसभा सत्र के दौरान इंजीनियरों द्वारा कमीशन मांगने का आरोप लगा कर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उस समय नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में 70-80 विधायक वेल में आ गये थे। एक खेमे ने तब माना था कि विधानसभा के सामने सड़क के उस पार भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बैठे तत्कालीन प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने हवा भरा था। नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और गाजियाबाद पुलिस आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला है।

बीमारू राज्य से अर्थ शक्ति बनकर उभरा यूपी

न्यूज़ डेस्क

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के आठ वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न लखनऊ में पत्रकार वार्ता की। और शासन का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले यूपी को बीमारू राज्य माना जाता था। लेकिन आज अर्थ शक्ति बनकर उभरा है। याद रहे यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं और दूसरी तरफ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व योगी को हटाने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में योगी का यह बयान बहुत कुछ कहता है। यूपी में कितना कुछ बदला है यह भी जांच का विषय हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दंगे व आतंक को लोगों ने देखा। आठ वर्ष पहले यूपी बीमारू राज्य माना जाता था। आज वही प्रदेश अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। पहले यूपी विकास का ब्रेकर माना जाता था।आज वही प्रदेश विकास का उदाहरण बनकर उभरा है। प्रदेश वही है, जनता वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ सरकार बदलने मात्र से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, आप सभी जानते हैं कि यहां की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, यह किसी से छिपा नहीं है। यही प्रदेश है, जहां किसान आत्महत्या करता था।युवाओं के सामने पहचान का संकट था। इसी प्रदेश में दंगा व अराजकता था। इन्हें प्रदेश ने झेला था। प्रदेश और तंत्र वही है, केवल सरकार बदलने से व्यापक बदलाव कैसे होता है, इसको महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया, उसकी वजह से जो प्रदेश बीमारू था, आज वही प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। आज प्रत्येक सेक्टर में प्रदेश देश के विकास में ब्रेक थ्रू के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान रहा। हमारे पास प्रकृति की ओर से प्रचुर मात्रा में अवसर था, हम इसको आगे बढ़ सकते थे। 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था, कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी।आज व्यापक बदलाव हुए, कृषि विकास दर 13.5 फीसदी से अधिक हुई, इससे प्रदेश के जीडीपी में 28 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई, इसकी शुरुआत हमारी पहली कैबिनेट ने किया था। 36 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी की गई।

सीएम ने कहा कि 2017 से 2023 तक हमने ढाई गुना ज्यादा गेहूं की खरीदारी की। 43 हजार 424 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसी प्रकार धान की खरीदारी के लिए 88 हजार 746 करोड़ डीबीटी के माध्यम से दिया गया। सरकार ने 32 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को बाढ़ से बचाने का कार्य किया गया।योगी ने कहा कि प्रदेश में निराश्रित गोवंश के लिए 7700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में 12 लाख 50 हजार से अधिक गोवंश का संरक्षण सरकार कर रही है, साथ ही सहभागिता योजना के माध्यम से 1 लाख 5 हजार पशुपालकों को 1 लाख 63 हजार गोवंश उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है। जिसके लिए सरकार 1500 रुपये प्रति गोवंश प्रति माह कर रही है।

इस मौके पर उन्होंने सरकार के आठ वर्षों की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद सरकार की 'सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति' पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की।

धामी सरकार के पूरे हुए तीन साल, कांग्रेस हुई हमलावर

न्यूज़ डेस्क

उत्तराखंड की धामी सरकार 2.0 के 3 साल पूरे होने पर जहां भाजपा सरकार जगह-जगह अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की खामिया गिनाई है। कांग्रेस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करन माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे. कांग्रेस के सभी नेताओं ने सरकार के 3 साल को निराशाजनक बताया. साथ ही खामियां गिनाई।

धामी सरकार पर फायर हुए हरदाः पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल होने जा रहा है। अगर इसमें भाजपा का पिछला कार्यकाल जोड़ें तो 8 वर्ष हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ग की जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। किसान, युवा, महिला, व्यापारी, वृद्धजनों के साथ भाजपा ने धोखा किया. इन वर्षों में भाजपा की कथनी और करनी में गंभीर अंतर रहा. प्रचार से जनता के असली सवालों से बचने का प्रयास किया गया। हरीश रावत ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, पलायन असली मुद्दा है। हरीश रावत ने आगे कहा कि, पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 6 दर्जन गांव भुतहा (घोस्ट विलेज) हैं। आज बेबसी और पलायन गंभीर समस्या बन गई है। राज्य के विकास में भी जबरदस्त असंतुलन दिखाई दिया। इनके प्रस्तावित बजट और जो क्रियान्वित हो रहा है, उसमें गंभीर अंतर है. जबकि कांग्रेस ने हमेशा जिला योजनाओं को महत्व दिया। हरीश रावत ने कहा कि, मनरेगा के अंदर प्राप्त धनराशि से लेकर सेंटर स्पांसर योजनाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। सिर्फ प्रचार के माध्यम से विफलताओं को ढकने की कोशिश की गई है। राज्य के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। 2016 में सड़कों पर जितने डेंजर प्वाइंट थे, उनकी संख्या बढ़कर आज तिगुनी हो गई है। यही कारण है कि रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। पीएमजीएसवाई की सड़कों का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठेकेदार मनमाने तरीके से कम कर रहे हैं।

हरीश रावत ने कहा कि सरकार का धामी एडिशन झूठ के गर्भ से पैदा हुआ है। इससे पूर्व त्रिवेंद्र एडिशन भी झूठ के गर्भ से पैदा हुआ था। यह सनातन के भी नहीं हैं. सनातन में परिवार को एक संस्था माना गया है. लेकिन इन्होंने लिव इन के जरिए उस संस्कृति पर भी हमला किया है। इसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इनकी राजनीति केवल घृणा द्वेष पर आधारित होती है। लोगों के अंदर घृणा पैदा करके द्वेष पैदा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के पास सशक्त यूनाइटेड अपोजिशन की क्षमता है। जब भी कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया. कांग्रेस ने माइलस्टोन बनकर काम किया। लोग अब झूठ और फरेब के गर्भ से पैदा हुई भाजपा को नकारेंगे। वहीं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बेरोजगारी, महंगाई और दलितों के उत्पीड़न का जिक्र किया। उन्होंने धामी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को विफलताओं का कार्यकाल बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दलित शोषित समाज और महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है। उत्तराखंड को अब भ्रष्टाचार के मॉडल के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि 2017 में उत्तराखंड पर 35 हजार करोड़ का कर्ज था ,लेकिन बीते 8 सालों में यह कर्ज बढ़कर 95 हजार करोड़ से ऊपर हो गया।

क्या मोहन लाल बड़ोली फिर बनेंगे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ?

न्यूज़ डेस्क

मोहन लाल बडौली की गिनती भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के करीबियों में होती है। लोकसभा, विधानसभा और शहरी निकाय चुनाव में मोहन लाल बडौली मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चले।इसके बावजूद राज्य में भाजपा के कई ऐसे नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के लिए मोहन लाल बडौली से भी ज्यादा करीबी हैं

हरियाणा का अगला बीजेपी प्रमुख कौन होगा इसका फैसला तो पार्टी हाईकमान को लेना है लेकिन जिस तरह से नेताओं की लॉबिंग चल रही है उससे तो यही लगता है कि मोहन लाल बडोनी को फिर से यह जिम्मेदारी मिल सकती है। बडोनी अभी हाल में ही पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। उन्ही मुलाकात पार्टी अध्यक्ष नड्डा से भी हुई है।

हालांकि बडोनी पर हिमाचल प्रदेश सेक्स कांड का भी इल्जाम है लेकिन बडोनी की राजनीतिक सूझबूझ से पार्टी कायल भी है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर उनके नाम की चर्चा खूब हो रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कसौली दुष्कर्म कांड में मोहन लाल बडौली का नाम सामने आया था ,हालांकि अभी उस कांड में बडोनी को क्लीन चिट मिल चुकी है। पार्टी को इस कांड के बाद काफी नुकसान भी हुआ था। भाजपा के शीर्ष नेताओं को जनता व विपक्ष में जवाब देना भारी हो रहा था। मोहन लाल बडौली लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उन्हीं के कार्यकाल में भाजपा ने लोकसभा की पांच और विधानसभा की 48 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा ने शहरी निकाय चुनाव में भी क्लीन स्वीप किया है।

मोहन लाल बडौली की गिनती भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के करीबियों में होती है। लोकसभा, विधानसभा और शहरी निकाय चुनाव में मोहन लाल बडौली मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चले।इसके बावजूद राज्य में भाजपा के कई ऐसे नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के लिए मोहन लाल बडौली से भी ज्यादा करीबी हैं और वे उनमें से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। इसकी संभावना तब ज्यादा बलवती हो गई, जब राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मनोहर लाल की गिनती पीएम मोदी और अमित शाह के बाद पार्टी के सबसे वरिष्ठ व विश्वसनीय नेताओं में होती है। मोहन लाल बडौली के ऊपर उनका भी आशीर्वाद है, लेकिन बडौली के अलावा आधा दर्जन नेताओं की उनकी कुर्सी पर निगाह है, जिस पर कब्जे के लिए वे अंदरुनी प्रयास करते नजर आ रहे हैं।

क्या पटरी पर आ रही है राजस्थान कांग्रेस?

न्यूज़ डेस्क

राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें बोतल की जिन्न की तरह बार-बार बाहर निकलती है। आंतरिक कलह और गुटबाजी की खबरों के बीच प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आलाकमान को पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देने के लिए एक कूटनीतिक दांव चला। रंधावा ने कांग्रेस के आठ सांसदों को दिल्ली आवास पर डिनर के लिए बुलाया।

प्रदेश प्रभारी रंधावा के डिनर में सांसद राहुल कस्वां, बृजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, उम्मेदाराम बेनीवाल, कुलदीप इंदौरा, भजनलाल जाटव और अनीता जाटव शामिल हुईं। साथ ही राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने डिनर का लुत्फ उठाया। यही नहीं इस डिनर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद थे। डिनर के साथ आयोजित बैठक में राजनीतिक चर्चा हु चर्चा में है कि राजस्थान से कांग्रेस के लोक सभा सांसद भी अलग-अलग गुटों में बंटे हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि सचिन पायलट खेमे में मुरारी लाल मीणा, हरीश चौधरी, बिजेंद्र ओला, कुलदीप इंदौरा शामिल हैं तो भजनलाल जाटव पूर्व सीएम अशोक गहलोत के समर्थक हैं।

अब आगे क्या कुछ होना है इसे देखना बाकी है। उधर एक और बड़ा फैसला सचिन पायलट को लेकर होने की बात कहि जा रही है। जानकारी के मुताबिक़ अहमदाबाद में होने जा रहे कांग्रेस अधिवेशन में सचिन को लेकर पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सचिन को पार्टी क्या बड़ी जिम्मेदारी देगी यह तो बाद में पता चलेगा लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक़ सचिन को मपट्र्य संगठन महासचिव बनाया जा सकता है। इस पद पर अभी केसी बेणुगोपाल है। कहा जा रहा है कि सचिन को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी राजस्थान से गुटबाजी को ख़त्म करना चाहती है ताकि पार्टी खुलकर आगे काम कर सके और राजस्थान में पार्टी का जनाधार बढ़ सके।

नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक कर रही लडकियां

न्यूज़ डेस्क

पंजाब में युवाओं के बीच नशा का सेवन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सूबे के हर जिले में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो नशे के शिकार हैं। हालांकि सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किये गए लेकिन युवाओं में नशे की लत घटने के बजाये बढ़ती ही चली गई। सरकार और प्रशासन भी नशा को रोकने ने अब तक असफल ही रही है। ऐसे में अब युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए लडकियां मैदान में उतरी हैं। लड़कियों ने थियेटर के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने की कमान संभाली है ।

द ओपन आर्ट थियेटर ग्रुप द्वारा नशों के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुत किए जा रहे नुक्कड़ नाटकों के सात कलाकारों में पांच लड़कियां शामिल हैं, जो विभिन्न स्कूल-कॉलेज की छात्राएं हैं। एक कलाकार पंजाब पुलिस का कर्मचारी है जो दिन-रात युवाओं को नशों के खिलाफ जागरूक कर रहा है। सूबे के हर इलाके में नाटक के जरिये नशे के खिलाफ अभियान चला रही है लडकियां। बड़ी बात यह है कि जहाँ -जहाँ लडकियां अपना नाट्य प्रदर्शन कर रही हैं वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लड़कियों की सराहना भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में टैक्सी ड्राइवर, मजदूर व अन्य लोग नाटक से प्रेरणा ले रहे हैं।

नाट्य कलाकारों में पंजाब पुलिस के सिपाही संदीप सिंह गैवी का कहना है कि अगर हमें पंजाब की जवानी को बचाना है तो अपने बच्चों को नशों से दूर रखना होगा। इसके साथ ही अन्य कलाकारों सुपनदीप सिंह के अलावा लड़कियों में ईशु सेठी, कुसुम कदम, स्नेहा वर्मा, परी सोनी, वैशाली वाटस आदि ने नाटक के माध्यम से संदेश दिया कि किस प्रकार नशे की यह लत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है और एक दिन पूरा घर तबाह हो जाता है। सभी कलाकारों ने अपनी कला की शानदार प्रस्तुति से लोगों को नशों से दूर रहने को प्रेरित किया।

नाटक के निर्देशक अतुल खुंगर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इससे युवाओं को नशों से दूर रहने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें ताकि वह बुरी संगत का शिकार होने से बच सकें। खुंगर ने बताया कि अबोहर में अब तक प्रस्तुत किए गए नाटकों के इतिहास में पहली बार इस नाटक में पांच लड़कियों ने एक साथ अभिनय किया है जो काबिले-तारीफ है।

न्यू देहली पोस्ट

अब अय्यपा मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर नया विवाद

न्यूज़ डेस्क

दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक अयप्पा मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर नया विवाद शुरू हुआ है। सदियों से चली आ रही प्रथा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। हालांकि, मंदिर प्रबंधन की सूझबूझ से मामला शांति से निपट गया है। अयप्पा मंदिर केरल राज्य के पत्तनमतिट्टा जिले में है। ये पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर सबरिमलय पहाड़ पर है। यह मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है। मंदिर के निर्माण की तिथि पर मतभेद हैं, लेकिन यह माना जाता है कि यह कई शताब्दियों पुराना है। मंदिर की वास्तुकला केरल वास्तु शैली में बनाई गई है, और इसमें भगवान अयप्पन की मूर्ति के अलावा अन्य देवताओं की मूर्तियां भी हैं। अयप्पा और सबरीमाला मंदिर दोनों एक ही मंदिर परिसर में स्थित हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है।

भगवान अयप्पन को समर्पित है.मंदिर का मुख्य गर्भगृह भगवान अयप्पन की मूर्ति को समर्पित है। यह मंदिर पुरुषों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां वे भगवान अयप्पन की पूजा करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं।

सबरीमाला मंदिर

यह मंदिर भगवान अयप्पन के अलावा अन्य देवताओं को भी समर्पित है। मंदिर परिसर में कई अन्य मंदिर और स्मारक हैं, जो विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं। सबरीमाला मंदिर एक विशाल मंदिर परिसर है, जो कई एकड़ में फैला हुआ है और इसमें कई मंदिर हैं।

अयप्पा मंदिर की कहानी बहुत प्रसिद्ध है और यह भगवान अयप्पा की कथा से जुड़ी हुई है। भगवान अयप्पा को भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र के रूप में पूजा जाता है। केरल के राजा राजशेखर को वो पंबा नदी के पास शिशु रूप में मिले थे। राजा राजशेखर ने अयप्पा भगवान से पूछकर ही मंदिर के निर्माण के लिए ये स्थान चुना था, जो आज सबरीमाला के नाम से जाना जाता है। मंदिर के निर्माण के बाद, राजा ने भगवान अयप्पा की मूर्ति स्थापित की और उनकी पूजा शुरू की। तब से, सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बन गया है और हर साल लाखों भक्त यहां आते हैं और भगवान अयप्पा की पूजा करते हैं। यह मंदिर पुरुषों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां वे भगवान अयप्पा की पूजा करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। पहले महिलाओं को 10 से 50 वर्ष की आयु के बीच मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यह नियम अब बदल गया है और महिलाएं भी मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं।

अयप्पा मंदिर में बगैर कपड़े पहने या नंगे पैर जाने की परंपरा एक विशेष महत्व रखती है। यह परंपरा भगवान अयप्पा की कथा से जुड़ी हुई है। भगवान अयप्पा की कथा के अनुसार, वे एक ऐसे स्थान पर रहते थे, जहां कोई भी वस्त्र नहीं पहनता था। इसलिए, भक्तों को भी बगैर कपड़े पहने या नंगे पैर जाने की परंपरा का पालन करना होता है, जो आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। मंदिर में बगैर कपड़े पहने जाने से यह संदेश दिया जाता है कि सभी लोग समान हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवान अयप्पा की कथा में कहा गया है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग किया था। इसलिए, भक्तों को भी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करने की प्रेरणा मिलती है और वे बगैर कपड़े पहने या नंगे पैर जाने की परंपरा का पालन करते हैं। अयप्पा मंदिर में बगैर कपड़े पहने जाने से यह संदेश दिया जाता है कि हमें प्राकृतिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए और आधुनिक जीवन की सुविधाओं का त्याग करना चाहिए।

केरल के पथनमथिट्टा स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में कुछ पुरुष श्रद्धालुओं ने लंबे समय से चली आ रही प्रथा का विरोध जताते हुए बिना कमीज उतारे मंदिर में प्रवेश किया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रवेश करने से पहले पुरुष श्रद्धालुओं के लिए कमीज उतारना अनिवार्य होने की प्रथा का विरोध जताने के लिए यह कदम उठाया। इस मामले की सामने आईं तस्वीरों में एसएनडीपी संयुक्त समारा समिति के सदस्य त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) द्वारा प्रबंधित पेरुनाडु में मंदिर के सामने कतार में खड़े और अपनी कमीज उतारे बिना प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का विरोध बिना किसी घटना के खत्म हो गया क्योंकि न तो पुलिस और न ही मंदिर प्रबंधन ने कोई आपत्ति जताई। प्रदर्शनकारियों ने बाद में मांग की कि पुरुष श्रद्धालुओं के ऊपरी वस्त्र उतारने की प्रथा को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

पवन कल्याण का संदेश किसके लिए है?

न्यूज़ डेस्क

आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने परिसीमन के मसले पर एक संदेश दिया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उनका संदेश भाजपा के लिए है या मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के लिए है। संदेश अधूरा रहे और छिपा हुआ रहे इसलिए पवन कल्याण ने एक ड्रामा रचा। वे चूंकि फिल्मी हस्ती हैं तो यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बुलावे पर अपना एक प्रतिनिधि चेन्नई भेज भी दिया और फिर उसको विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने से रोक भी दिया। इस तरह उन्होंने यह संदेश तो दिया है कि वे समय आने पर स्वतंत्र राजनीति भी कर सकते हैं।

असल में स्टालिन ने 22 मार्च को केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित परिसीमन पर विचार करने के लिए सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इसमें हिस्सा लेने के लिए पवन कल्याण की पार्टी के सांसद टी उदय श्रीनिवास 21 मार्च को चेन्नई पहुंच गए। चेन्नई हवाईअड्डे पर डीएमके सांसदों विल्सन और किरिराजन ने श्रीनिवास का स्वागत किया। यह बहुत हैरान करने वाली बात थी क्योंकि पवन कल्याण की पार्टी एनडीए का हिस्सा है और केंद्र की एनडीए सरकार की ओर से प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ बैठक होने वाली थी। फिर भी उन्होंने बैठक का समर्थन करते हुए अपना प्रतिनिधि भेजा। लेकिन अगले दिन 22 मार्च की बैठक से उनका सांसद नदारद रहा। कहा जा रहा है कि पवन कल्याण ने ही अपने प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने से रोक दिया। उनका मकसद सिर्फ यह दिखाना था कि वे स्वतंत्र राजनीति भी कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आंध्र प्रदेश में और एनडीए नेतृत्व में इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है।

हनी ट्रैप में फंसे है कई केंद्रीय मंत्री

कर्नाटक विधानसभा में बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। राज्य सरकार के मंत्री केएन राजन्ना ने आरोप लगाया है कि कम से कम 48 नेता हनी ट्रैप में फंस गए हैं। हनी ट्रैप का मतलब होता है किसी न किसी तरह से महिलाओं द्वारा पुरुषों को मोहपाश में फंसाना है। कई बार जाल बिछा कर किसी को हनी ट्रैप में फंसाया जाता है तो कई बार लोग खुद अपनी आदतों और आचरण से ऐसे जाल में फंसते हैं। कर्नाटक सरकार के मंत्री ने यह साफ नहीं किया है कितने लोग अपनी आदतों के कारण इस जाल में फंसे हैं और कितने लोगों को जाल बिछा कर योजना के तहत फंसाया गया है। लेकिन उनके आरोप गंभीर है।

कर्नाटक सरकार के मंत्री ने यहां तक कहा है कि फंसे हुए 48 लोगों में कई राष्ट्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री राजन्ना के आरोपों का राज्य के गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर ने समर्थन किया। कहा जा रहा है कि 48 नेताओं की सीडी और पेन ड्राइव बनी हुई है, जो कभी भी सार्वजनिक हो सकती है। सीडी और पेन ड्राइव के आधार पर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है।

ध्यान रहे कर्नाटक में पहले भी पेन ड्राइव और सीडी सामने आते रहे हैं। कई लोग तो कर्नाटक को हनी ट्रैप की सीडी की फैक्टरी बताते हैं। कुछ समय पहले ही भाजपा की सहयोगी जेडीएस के नेता एचडी देवगौड़ा के पोते और पार्टी के सांसद की सेक्स सीडी सार्वजनिक हुई थी, जिसके बाद वे गिरफ्तार हुए थे। जो हो लेकिन यह आरोप गंभीर है कि प्रदेश के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी इसमें फंसे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को भी पहल करके इस मामले की जांच करानी चाहिए।

तमिलनाडु में क्या फिर से बीजेपी और अन्नाद्रमुक एक साथ आएंगे?

न्यूज़ डेस्क

तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अन्नाद्रमुक और बीजेपी ने गठबंधन के लिए औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। ईपीएस के नाम से मशहूर एआईएडीएमके नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों की यह पहली औपचारिक बातचीत थी। इस मुलाकात से पहले दोनों दलों के नेताओं ने कई हफ्ते तक अनौपचारिक बातचीत की थी। गठबंधन की औपचारिक घोषणा से पहले दोनों दलों में दो-तीन राउंड की और बातचीत होने की संभावना है। पलानीस्वामी एआईएडीएमके के उन नेताओं में शामिल रहे हैं, जो बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे लेकिन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से उन्होंने अपना मन बदल दिया है। इससे पहले एआईएडीएमके ने बीजेपी से तब समझौता किया था, जब उसकी सबसे बड़ी नेता जे जयललिता का निधन हो गया था और पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई थी। उस समय एआईएडीएमके सरकार के कई फैसलों पर बीजेपी का प्रभाव नजर आया था। साल 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके को मिली भारी जीत के बाद पलानीस्वामी ने बीजेपी से दूरी बना ली। सितंबर 2023 में यह गठबंधन टूट गया था।

पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में एमके स्टालिन की डीएमके और उनके साथी दलों ने शानदार प्रदर्शन किया था। डीएमके ने उपचुनावों और नगर निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज की.इससे डीएमके नेता एमके स्टालिन दक्षिण में बीजेपी विरोधी विपक्ष के चेहरे के रूप में स्थापित हो गए , इसने पलानीस्वामी को अपना मन बदलने के लिए मजबूर किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एआईएडीएमके चाहती है कि बीजेपी के साथ गठबंधन की निगरानी के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन हो। यह कमेटी तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई से ऊपर होगी। दरअसल इससे एआईएडीएमके यह संदेश देना चाहती है कि वह सीधे बीजेपी हाई कमान से बात कर रहा है। दरअसल दोनों दलों का गठबंधन टूटने की वजह अन्नामलाई का एआईएडीएमके नेताओं पर जुबानी हमलों को माना जाता है। लगातार हमलों को 2023 में गठबंधन टूटने के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन से पहले एआईएडीएमके अन्नामलाई को हटाने की मांग कर रही थी। लेकिन बीजेपी ने इस मांग को अनसुना कर दिया था। इस वजह से यह गठबंधन नहीं हो पाया था।

ओडिशा में आज भी हो रहे हैं बाल विवाह

न्यूज़ डेस्क

कहने को तो देश में बाल विवाह निषेध कानून है लेकिन परंपरा और गरीबी के सामने कोई कानून की क्या औकात हो सकती है ? कहने को तो देश में और भी बहुत सारे कानून हैं लेकिन उसका पालन कौन करता है ? बड़ी बात तो यह है कि जिस संसद और विधान सभाओं में कानून बनाने का ढोंग किया जाता है उसी संसद और विधान सभाओं में कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाले माननीय भी बैठे होते हैं और बड़ी बात कि वे जनता और समाज के हित के लिए कानून भी बनाते हैं।

इसी देश में संविधान में साफ़ दर्ज है कि भारत एक सेक्युलर देश है जहां हर जाति और धर्म मानने वालों को सामान अधिकार है। पुरुष के बराबर महिला है। संविधान यह भी कहता है कि कली भी किसी धर्म के खिलाफ और मानव समाज के खिलाफ ऐसा माहौल नहीं खड़ा करेगा जिससे समाज में खाई पैदा हो। संसद और सदन मढे बैठने वाले सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदाचारी होंगे और न झूठ बोलेंगे और न ही अपराधी प्रवृति के होंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं। संसद का माहौल क्या है और संसद में बैठने वाले लोग किस आचरण के हैं यह कौन नहीं जानता ? यह सब होते हुए भी देश चल रहा है और हम सब एक हैं। एक नहीं भी हैं तो एक होने का ढोंग तो कर ही लेते हैं और यही भारत की महानता है और नेताओं का बड़प्पन भी। हाँ तो हम चर्चा कर रहे थे कि बाल विवाह पर हमारे देश में रोक लगी हुई है और इसके लिए कठोर सजा की भी व्यवस्था है। लेकिन ओडिशा से जो जानकारी आ रही है वह चौंकाने वाली है। खबर ये है कि है

ओडिशा में प्रतिदिन तीन बाल विवाह होते हैं। सूबे का नबरंगपुर जिला 1,347 मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर है तो गंजम जिला 966 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। जबकि कोरापुट 636 मामलों के साथ तीसरे स्थान ;पर है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 से अब तक ओडिशा में 8,159 बाल विवाह हुए हैं। ये सब क्यों हुए और कैसे हुए इसकी जानकारी सदन को होती है। नेताओं को होती है और बड़ी बात कि सरकार के लोगों को भी होती है। लेकिन इस पर कोई रोक नहीं। आखिर रोक लगाए भी कौन ? जब कोई भी सरकार गरीबी को ख़त्म नहीं कर सकती ,शिक्षित समाज का निर्माण नहीं कर सकती और जनता की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सकती तो वह कैसे किसी गरीब माँ बाप को उसके कर्म से रोक सकती है ?

ऐसा नहीं है कि सरकारी तंत्र बाल विवाह को रोकने का प्रयास नहीं करती लेकिन यह प्रयास केवल प्रचार तक ही सीमित है। एक्शन में कुछ भी नहीं। यही वजह है कि ओडिशा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रशासन द्वारा की गई कई पहलों के बावजूद, पिछले छह वर्षों के दौरान ओडिशा में हर दिन कम से कम तीन ऐसे मामले सामने आए हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता इस चौंकाने वाले आंकड़े के लिए आदिवासी प्रथा, दहेज, मजदूर परिवारों के पलायन और माता-पिता के इस डर को जिम्मेदार मानते हैं कि बेटियाँ भाग सकती हैं।आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 से फरवरी 2025 तक ओडिशा में 8,159 बाल विवाह हुए हैं। उनमें से, नबरंगपुर में 1,347 मामले सामने आए हैं, जो उस अवधि के दौरान ओडिशा के सभी 30 जिलों में सबसे अधिक है।

गंजम जिला 966 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि कोरापुट 636 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद मयूरभंज (594), रायगढ़ (408), बालासोर (361), क्योंझर (328), कंधमाल (308) और नयागढ़ (308) का स्थान है।इन छह वर्षों में झारसुगुड़ा जिले में सबसे कम 57 मामले पाए गए हैं।सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि कि , "बाल विवाह को रातों-रात पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। हमें लड़कियों और उनके माता-पिता के लिए ऐसा माहौल और समाज बनाना होगा, ताकि वे ऐसे कदम न उठाएं।"

वे यह भी मानते हैं कि कम उम्र के बच्चों की शादी आदिवासियों की एक पारंपरिक प्रथा है, खासकर विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के लिए। जानकार कहते हैं कि माता-पिता जो आमतौर पर आजीविका के लिए दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, वे भी अपनी लड़कियों की शादी कानूनी उम्र से पहले कर देते हैं, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो और उनकी सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि लड़की किसी के साथ भाग सकती है, जिससे परिवार की बदनामी हो सकती है।

सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि दहेज भी ऐसी शादियों का कारण है, क्योंकि दुल्हन जितनी बड़ी होती है, उतनी ही ज़्यादा मांग होती है। अगर हम उन्हें उचित शिक्षा या कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम हों, ताकि वे स्व-रोजगार कर सकें, तो यह समस्या समाप्त हो सकती है, ताकि उन्हें यह न लगे कि लड़कियों के भविष्य के लिए शादी ही एकमात्र कदम है। एक अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए ओडिशा सरकार हर तीन महीने में पंचायत, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत कार्यकारी अधिकारी और आवासीय छात्रावासों के वार्डन/मैट्रन को मुख्य विवाह निषेध अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसी तरह, सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रमुखों को मुख्य विवाह सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, अधिकारी ने कहा। इसके अलावा, सरकार हर छह महीने में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय समितियों की बैठकें आयोजित कर रही है। कम उम्र में विवाह के साथ-साथ, राज्य बाल श्रम की चुनौती से भी जूझ रहा है।

ओडिशा सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए पंचायत अधिकारियों और वार्डन को सीएमपीओ शक्ति प्रदान की। इन छह वर्षों में, अधिकारियों ने मजदूरी कर रहे 328 बच्चों को बचाया है। आंकड़ों से पता चला है कि 2019-20 में जहां 85 बच्चों को बचाया गया, वहीं 2020-21 और 2021-22 में यह संख्या क्रमशः चार और 43 थी। इसी तरह, 2022-23 में राज्य के विभिन्न हिस्सों से 107 और अगले साल 44 बाल मजदूरों को बचाया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 फरवरी तक अधिकारियों ने ओडिशा के विभिन्न जिलों से 45 बाल मजदूरों को बचाया है।

संभव है कि ये सब गरीबी और अशिक्षा की वजह से हो रहे हैं। आगे भी होते रहेंगे। इसका खात्मा तो तभी हो सकता है जब समाज से असमानता जाएगी और लोगो का जीवन स्तर ऊंचा होगा। शिक्षा दर में बढ़ोतरी होगी और लड़कियों को बेहतर जीवन जीने का माहौल मिलेगा। लेकिन ऐसा है क्या ? बाल विवाह की कहानी ओडिशा तक ही सीमित नहीं है। देश के कई इलाकों में यह प्रथा आज भी धड़ल्ले से जारी है। कई विवाह में गतो नेता जन भी उपस्थित होते देखे गए हैं। राजस्थान ,बिहार और झारखंड के अलावा कई और भी राज्य हैं जहाँ बाल विवाह पर कोई रोकथाम नहीं। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और उन लोगों को भी अपने बच्चो को कम उम्र में न शादी करने पर सोचने की जरूरत है जो हमेशा यह कहते रहते है कि परंपरा और प्रथा के साथ ही गरीबी की वजह से वे ऐसा कर रहे हैं।

अगर ओडिशा के साथ ही देश पर भी नजर डाले तो चैंकाने वाले आंकड़े समने आते हैं । भारत में 2011 के बाद अब तक देश में कोई जनगणना नहीं हुआ है लेकिन 2011 के जनगणना के विश्लेषण से एक आंकड़ा चौंकाता है और सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाता है। देशवार ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश में आज भी अशिक्षा और गरीबी की चलते कितने मासूमो की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 12 मिलियन भारतीय बच्चों की शादी दस वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। इन बच्चों में 84 फीसदी हिन्दू और करीब 11 फीसदी मुस्लिम बच्चे थे।

आंकड़े यह बता रहे हैं कि 12 मिलियन बच्चों में से 7.84 मिलियन (65%) विवाहित बच्चों में से अधिकांश लड़कियाँ थीं। इसके साथ ही 10 में से आठ अशिक्षित बच्चे भी लड़कियाँ थीं।आंकड़े यह भी बताते हैं कि 10 वर्ष से पहले विवाहित सभी हिंदू लड़कियों में से 72% ग्रामीण क्षेत्रों में थीं, जबकि 58.5% मुस्लिम लड़कियाँ थीं, जिनमें उच्च शिक्षा का स्तर बाद में विवाह से संबंधित था।

आंकड़ों के मुताबक जैन महिलाएँ सबसे बाद में शादी करती हैं (20.8 वर्ष की औसत आयु में), उसके बाद ईसाई महिलाएँ (20.6 वर्ष) और सिख महिलाएँ (19.9 वर्ष) आती हैं। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की पहली शादी की औसत आयु सबसे कम (16.7 वर्ष) है। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 12 या उससे अधिक वर्षों की शिक्षा प्राप्त महिलाओं की तुलना में बिना शिक्षा वाली महिलाओं में किशोरावस्था में गर्भधारण और मातृत्व का स्तर नौ गुना अधिक है।

10 वर्ष से कम आयु के 5.4 मिलियन (44%) विवाहित बच्चे अशिक्षित थे - उनमें से 80% लड़कियाँ थीं। इस आंकड़े से यह भी पता चलता है कि शिक्षा का निम्न स्तर कम आयु में विवाह से कैसे संबंधित है। प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में 1,403 लड़कियाँ कभी किसी शैक्षणिक संस्थान में नहीं गईं। सरकार लड़कियों को आगे बढ़ाने अजर पढ़ाने के लिए कहने को कई योजनाएं चला रही है लेकिन समुचित प्रबंधन के अभाव में लड़किया आगे नहीं पढ़ पा रही है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार भारत में लड़की 18 वर्ष की आयु से पहले और लड़का 21 वर्ष की आयु से पहले विवाह नहीं कर सकता।गुजरात उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अलग-अलग निर्णयों में उल्लेख किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त करने या 15 वर्ष की आयु पूरी करने पर विवाह कर सकती है।

2011 में 102 मिलियन लड़कियां (महिला आबादी का 30%) 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित थीं; 2001 में यह संख्या 119 मिलियन थी (महिला आबादी का 44%), जो कि दशक भर में 14 प्रतिशत अंकों की कमी है।लड़कों में, 2011 में 125 मिलियन लड़के 21 वर्ष की आयु से पहले विवाहित थे (पुरुष आबादी का 42%); 2001 में यह संख्या 120 मिलियन थी (पुरुष आबादी का 49%), जो कि दशक भर में 7 प्रतिशत अंकों की कमी है।

भारत का यह ऐसा सच है जो सरकार और सरकार की नीतियों पर तो तमाचा मरता ही है सरकार के उस नारे को भी झूठा साबित करता ही जिसमें कहा जाता है कि भारत विकसित देश के दौर में है और जल्द ही भारत दुनिया के विकसित देशों की सूची में शामिल हो जाएगा।

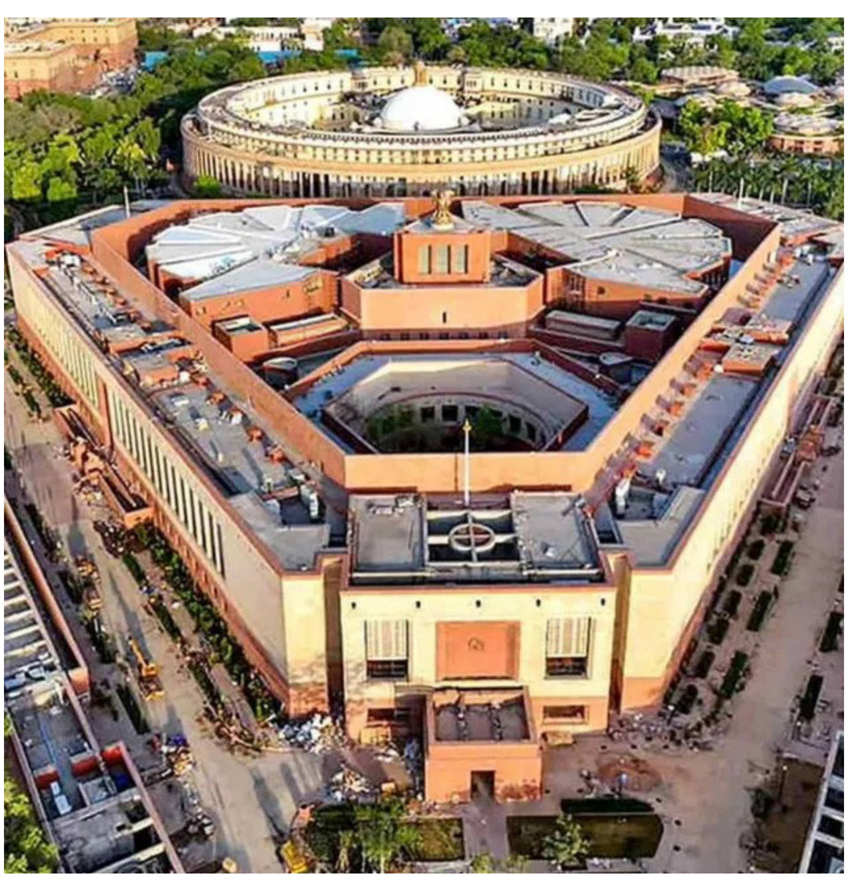

हर भारतीय भाषा में मिलेगी संसद की डिबेट

न्यूज़ डेस्क

अब संसद में होने वाली डिबेट हर भारतीय भाषा में आसानी से मिल सकेगी। इससे रिसर्चर्स, सांसदों और अन्य लोगों को फायदा होगा।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इंडियाएआई मिशन और लोकसभा के बीच समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। इसके तहत एआई का उपयोग करके संसद में होने वाले डिबेट का हर भारतीय भाषा में 'एआईकोष' के नाम से डेटासेट बनाया जाएगा। इससे संसद में होने वाली डिबेट का ट्रांसक्रिप्शन किसी भी भाषा में लिया जा सकेगा।वैष्णव ने आगे कहा कि इससे हमारे रिसर्चर्स, सांसदों और अकादमिक से जुड़े लोगों को संसद की डिबेट का विस्तृत ट्रांसक्रिप्शन किसी भाषा में मिल पाएगा।

बता दें कि मोदी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2024 में 10,300 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 'इंडिया एआई मिशन' को मंजूरी दी थी।

मोदी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए २०२४ में 10,३00 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 'इंडिया एआई मिशन' को मंजूरी दी थी।

इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य एक कॉम्प्रीहेन्सिव इकोसिस्टम तैयार करना है, जो कि कंप्यूटर तक पहुंच में लोकतंत्रीकरण, डेटा की गुणवत्ता को सुधार कर, स्वयं की एआई क्षमताएं विकसित कर, शीर्ष एआई टैलेंट, इंडस्ट्रीज के बीच साझेदारी, स्टार्टअप को रिस्क कैपिटल उपलब्ध कराने, समाज में बदलाव लाने वाले एआई प्रोजेक्ट के जरिए एआई इनोवेशन को बढ़ाना है। मोदी सरकार ने 2023 में तीन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया था, जो कि स्वास्थ्य, कृषि और सस्टेनेबल शहरों के क्षेत्र में बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने 2025 में बजट में शिक्षा के क्षेत्र में नया सीओई बनाने का ऐलान किया है।

न्यू देहली पोस्ट

क्या भारत में टीबी बीमारी इस साल के अंत तक ख़त्म हो पायेगा ?

हेल्थ डेस्क

पोलियो बीमारी को तो भारत ने ख़त्म कर दिया और इसकी सराहना अब दुनिया भर के देश भी कर रहे हैं लेकिन जिस टीबी बीमारी को 2025 तक ख़त्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा था क्या उसमे कामयाबी मिल पाएगी? यह बात इसलिए कही जा रही है कि भारत में टीबी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह बीमारी वहां तक भी पहुँच गई है जहां इसकी पहुँच नहीं थी। निर्धारित लक्ष्य पर गंभीरता से काम करके और लोगों में जागरूकता बढ़ाकर पिछले दो दशकों में भारत ने कई गंभीर बीमारियों पर विजय पाई है। पोलियो पर भारत की विजय ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इसी क्रम में भारत साल 2025 तक तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी रोग के उन्मूलन के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है, हालांकि ये राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही है।

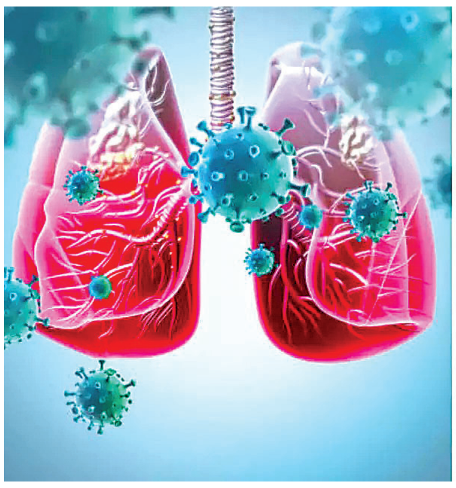

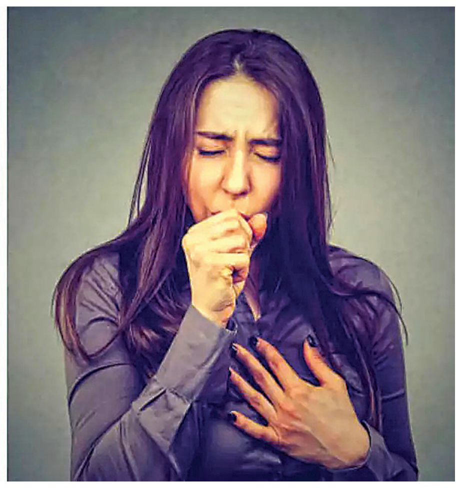

फेफड़ों में होने वाले इस गंभीर संक्रमण से हर साल दुनियाभर में लाखों लोग प्रभावित होते हैं, भारत के लिए भी ये बीमारी चिंता का कारण बनी हुई है। भारत से टीबी को अगले साल तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था हालांकि इसके मरीज हर साल बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत में 25.37 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए। इससे पहले 2022 में करीब 24.22 लाख लोगों में इस बीमारी का पता चला था। ज्यादातर मामले सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए, निजी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में मामलों को निदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें ये बीमारी तो है पर उनका निदान नहीं किया गया है जिससे संक्रमण के और भी बढ़ने का खतरा रहता है।

टीबी के मरीज दुनियाभर में देखे जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट में बताया कि साल 2023 में दुनियाभर में 8 मिलियन (80 लाख) से अधिक लोगों में तपेदिक का पता चला है। यह संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा 1995 में ट्रैक रखना शुरू करने के बाद से दर्ज किए गए मामलों की सबसे अधिक संख्या है। इससे पहले 2022 में डब्ल्यूएचओ ने टीबी के 7.5 मिलियन (75 लाख) मामले दर्ज किए। पिछले साल लगभग 1.25 मिलियन (12.5 लाख) लोगों की टीबी से मृत्यु भी हुई है।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्येयियस ने एक बयान में कहा, टीबी अभी भी इतने लोगों को बीमार कर रहा है और लाखों लोगों की मौत हो रही है, ये निश्चित ही चिंताजनक है। हमारे पास इसे रोकने, इसका पता लगाने और इलाज करने के उपकरण हैं फिर भी ये बीमारी लगातार बढ़ रही है, जो वास्तव में परेशान करने वाली स्थिति है। टीबी से संबंधित मौतों की संख्या में मामूली गिरावट जरूर आई है। साल 2022 में 1.32 मिलियन (13.2 लाख) मौतों से घटकर साल 2023 में यह 1.25 (12.5 लाख) रह गई है, लेकिन नए संक्रमितों की संख्या बढ़ना गंभीर विषय है।

भारत की बात करें तो यहां सामने आने वाले मामले अब भी वैश्विक टीबी का लगभग 25% हिस्सा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर व्यावसायिक जोखिमों को रेखांकित करते हुए एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में सामान्य आबादी की तुलना में स्वास्थ्य कर्मियों के बीच टीबी के मामले बहुत अधिक हैं।साल 2004 से 2023 के बीच किए गए 10 अलग-अलग अध्ययनों के विश्लेषण से पता चला है कि भारत में प्रति एक लाख स्वास्थ्य कर्मियों पर औसतन 2,391.6 मामले हैं। टीबी कई तरह से स्वास्थ्य के लिए गंभीर माना जाता है जिससे बचाव के उपाय करते रहना बहुत जरूरी है।

टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। ये मुख्य रूप से वायु जनित ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। टीबी रोग वाले लोगों की खांसी या छींक से निकलने वाले बूंदों के माध्यम से आसपास के अन्य लोगों में संक्रमण का खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, दो सप्ताह से अधिक समय तक अगर खांसी की दिक्कत बनी रहती है और कफ या खून आता है, सीने में दर्द, कमजोरी या थकान की समस्या रहती है तो ये टीबी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में टीबी के कारण वजन कम होने, भूख कम लगने, ठंड लगने, बुखार और रात में पसीना आना की भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपमें भी इस तरह के लक्षण हैं तो तुरंत इसकी जांच कराएं। टीबी रोग का समय पर इलाज होने से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है।

सप्ताह में 55 -60 घंटे से ज्यादा काम करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

हेल्थ डेस्क

इस साल के आर्थिक समीक्षा में वित्त मंत्री सीतारमण ने अलग से मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक रिपोर्ट पेश किया है। इस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि सप्ताह में 55-60 घंटे से ज्यादा काम करना मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही, अच्छे मैनेजर और सहकर्मियों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने खराब मैनेजर/सहकर्मियों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में 100-पॉइंट ज्यादा मेंटल वेल-बीइंग स्कोर की रिपोर्ट करते हैं। जो कर्मचारी अपने काम पर सबसे ज्यादा गर्व और उद्देश्य की रिपोर्ट करते हैं, उनका मेंटल वेल-वींग स्कोर 100-पॉइंट ज्यादा और सबसे खराब रिपोर्ट करने वालों की तुलना में 120-पॉइंट ज्यादा होता है। इसके अलावा, पूरी तरह से रिमोट वर्क कंडीशन में काम करने वाले व्यक्तियों का मेंटल वेल-बींग स्कोर पूरी तरह से इन-पर्सन या हाइब्रिड वर्क मॉडल में अपने काउंटरपार्ट्स की तुलना में करीब 50 पॉइंट कम होता है, जो ये बताता है कि मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए काम के दौरान सोशल इंटरैक्शन बहुत जरूरी है।

इतना ही नहीं, हफ्ते में 70-90 घंटे तक काम करने को लेकर जारी बहस के बीच शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक समीक्षा ने स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। समीक्षा में सेपियन लैब्स सेंटर फॉर ह्यूमन ब्रेन एंड माइंड की एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा गया, ''कहा गया कि डेस्क पर लंबा समय बिताना कर्मचारी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जो व्यक्ति डेस्क पर रोजाना 12 या इससे ज्यादा समय बिताता है, उसे मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों से जूझना पड़ता है।'' समीक्षा में कहा गया, ''काम पर बिताए गए घंटों को आमतौर पर उत्पादकता का एक उपाय माना जाता है, लेकिन पिछली रिपोर्ट से साफ हो गया है कि हफ्ते में 55-60 घंटे से ज्यादा काम करने का सेहत पर बुरा असर हो सकता है।''

डायबिटीज से दिल की बीमारी के साथ ही हड्डियों और जोड़ों को भी नुकसान

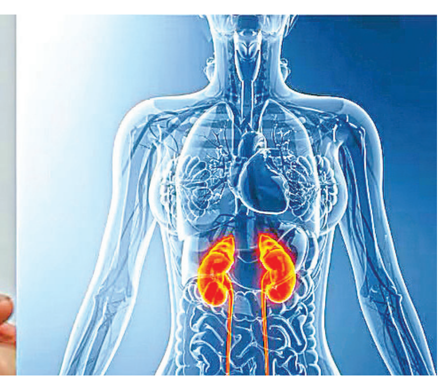

हेल्थ डेस्क

डायबिटीज के कारण न केवल स्ट्रोक या दिल से जुड़ी बीमारी होते हैं, बल्कि हड्डियों और जोड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। हाइपरग्लाइसेमिया या काफी ज्यादा ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने के कारण हड्डियों के कमजोर होने, जोड़ों में दर्द और फिजिकल एक्टिवा अपने आप कम होने लगती है। जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस और फ्रोजन शोल्डर (चिपकने वाला कैप्सूलाइटिस जिसके कारण कंधे के जोड़ में हरकतें सीमित हो जाती हैं) जैसी गंभीर स्थिति होने लगती है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों में घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस और लिगामेंट फैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को अपनी जोड़ों की खास देखभाल जरूर करनी चाहिए।

कमजोर हड्डियां- डायबिटीज हड्डियों के बनने और टूटने के बीच संतुलन को बाधित करता है। जिससे हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनमें फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। जोड़ों में दर्द और अकड़न - हाइपरग्लाइसेमिया के कारण जोड़ों में सूजन होती है. जिसके परिणामस्वरूप दर्द, अकड़न और गतिशीलता में कमी आती है। इसलिए, व्यक्ति को दैनिक कार्य आसानी से करने में कठिनाई होगी।

देरी से ठीक होना – मधुमेह के कारण अपर्याप्त रक्त प्रवाह फ्रैक्चर और जोड़ों की चोटों को ठीक करने की दर को कम करता है।

ऑस्टियोआर्थराइटिस का बढ़ा हुआ जोखिम- मधुमेह रोगियों को ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित होने का अधिक जोखिम होता है। खासकर घुटनों में, वजन बढ़ने, सूजन और जोड़ों को नुकसान के कारण, जिससे घिसाव होता है।

फ्रोजन शोल्डर – मधुमेह एक ऐसी स्थिति को भी आमंत्रित करता है जिसे एडहेसिव कैप्सूलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर के रूप में जाना जाता है। जिससे कंधे के जोड़ में अत्यधिक अकड़न और दर्द होता है।

लिगामेंट की चोट - ऊंचा ग्लूकोज स्तर लिगामेंट को कमजोर करता है, जिससे मधुमेह के व्यक्ति को चोट लगने की संभावना अधिक होती है जिसके लिए तुरंत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

डायबिटीज के शिकार लोग कैल्शियम और विटामिन से भरपूर फूड आइटम को अपनी डाइट का हिस्सा बनाए। आप अपने डाइट में डेयरी उत्पाद, पत्तेदार सब्जियां, मेवे और मछली का सेवन करें। इसी तरह, सूजन को कंट्रोल करने के लिए चीनी और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। रोजाना वजन उठाने वाली गतिविधियां जैसे चलना, प्रतिरोध प्रशिक्षण और योग हड्डियों की मजबूती और जोड़ों के लचीलेपन को बेहतर बना सकते हैं। जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए साइकिल चलाना और तैरना भी उपयुक्त है। धूम्रपान और शराब पीना बंद करें और जोड़ों पर दबाव कम करने के लिए अपने वजन को सही रखें।

गर्मियों में ऐसे करें दुधारू पशुओं की देखभाल

कृषि डेस्क

गर्मियों में पशुओं की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तर-पश्चिमी भारत में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और लंबे समय तक होती है। यहां गर्मियों में तापमान 45 डिग्री के पार चला जाता है। ऐसे मौसम में पशु दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। इस दबाव की स्थिति का पशुओं की पाचन प्रणाली और दूध उत्पादन क्षमता पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। इस मौसम में नवजात पशुओं की देखभाल में अपनायी गयी तनिक सी भी असावधानी उनकी भविष्य की शारीरिक वृद्धि, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन क्षमता पर स्थायी कुप्रभाव डाल सकती है। गर्मी में पशुपालन करते समय ध्यान न देने पर पशु के सूखा चारा खाने की मात्रा में 10 से 30 प्रतिशत और दूध उत्पादन क्षमता में 10 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। साथ ही साथ अधिक गर्मी के कारण पैदा हुए ऑक्सीकरण तनाव की वजह से पशुओं की बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी क्षमता पर बुरा असर पडता है और आगे आने वाले बरसात के मौसम में वे विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जिससे उनकी उत्पादन व प्रजनन क्षमता में गिरावट आ जाती है।

इस मौसम में सांड़ों की प्रजनन क्षमता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। सांड़ों में वीर्य उत्पादन व गुणवत्ता में कमी आती है। भैंसों में यह दुष्प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। उनके शरीर का काला रंग तथा बालों की कमी उष्मा को अधिक अवषोषित करती है। इसके अतिरिक्ति भैंसों में पसीने की ग्रन्थियाँ गायों की अपेक्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण भैंसों को शरीर से उष्मा निकालने में अधिक कठिनाई होती है। ऐसे गरम वातावरण में मादा पशुओं का मद चक्कर का काल लम्बा हो जाता है और मदावस्था का काल एवं उग्रता दोनों ही काफी मद्धिम पड़ जाते हैं तथा पशुओं में अमादकता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। पशुओं के लिए आवास हेतु साफ-सुथरी व हवादार पशुशाला होनी चाहिए जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो तथा मूत्र व पानी की निकासी हेतु ढलान हो। पशुशाला की छत ऊष्मा की कुचालक हो ताकि गर्मियों में अत्यधिक गर्म न हो। इसके लिए एस्बेस्टस सीट उपयोग में लायी जा सकती है। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास-फूस की परत या छप्पर ड़ाल देना चाहिए। ये परत उष्मा अवरोधक का कार्य करती है जिसके कारण पशुशाला के अन्दर का तापमान कम बना रहता है। सूर्य की रोशनी को परावर्तन करने हेतु पशुशाला की छत पर सफेद रंग करना या चमकीली एल्युमिनियम शीट लगाना भी लाभप्रद पाया गया है। पशुओं के आवास गृह में अधिक भीड़-भाड़ नही होनी चाहिए। प्रत्येक पशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराएं। एक वयस्क गाय व भैंस को 40 से 50 वर्गफुट स्थान की आवश्यकता होती है। मुक्त घर व्यवस्था में गाय व भैंसों को क्रमषः 35 व 40 वर्ग मीटर स्थान ढ़का हुआ तथा 7 व 8 वर्ग मीटर खुले बाड़े के रूप में प्रति पशु उपलबध होना चाहिए। पशुओं के शरीर पर दिन में तीन या चार बार जब वायुमंडल तापमान अधिक हो, ठंड़े पानी का छिड़काव करें। यदि सम्भव हो तो तालाब व जोहड़ में भैसों को ले जाएं। प्रयोगों से यह साबित हुआ है कि दोपहर को पशुओं पर ठंड़े पानी का छिड़काव उनके उत्पादन व प्रजनन क्षमता को बढ़ानें में सहायक होता है।

गर्मियों में पशु चारा चरना कम कर देते है। गर्मियों में जल वायुमंडलीय तापमान पशुओं के शारीरिक तापमान से अधिक हो जाता है तो पशु सूखा चारा खाना कम कर देते है क्योंकि सूखा चारा को पचाने में शरीर में उष्मा का अधिक मात्रा में निकलता है। अतः पशुओं को चारा प्रातः या सांयकाल में ही उपलब्ध कराना चाहिए तथा जहां तक संभव हो पशुओं के आहार में हरे चारे की मात्रा अधिक रखें। गर्मी में पशुपालन करते समय पशुओं को हरे चारे की अधिक मात्रा उपलब्ध कराना के दो लाभ हैं, एक तो पशु अधिक चाव से स्वादिष्ट एवं पौष्टिक चारा खाकर अपनी उदरपूर्ति करता है, तथा दूसरा हरे चारे में 70-90 प्रतिशत तक पानी की मात्रा होती है, जो समय-समय पर जल की पूर्ति करता है। गर्मी के मौसम में पशुओं को भूख कम लगती है और प्यास अधिक। इसलिए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दिन में कम से कम तीन बार पानी पिलाना चाहिए. जिससे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. इसके अलावा पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक एवं आटा मिलाकर पानी पिलाना चाहिए। पीने के लिए ठंड़ा पानी उपलब्ध कराना चाहिए।

लाभकारी है ये एग्रीकल्चर आधारित उद्यम

कृषि डेस्क

हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है जहां पर ऐसे हजारों बिजनेस है जो कृषि से संबंधित है और वर्तमान समय में यह एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जो बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है और जहां पर व्यवसाय के हजारों विकल्प मौजूद है। इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे बिजनेस है जिसे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं मगर इसके साथ ही कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जिनके लिए आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। अगर आपके अंदर भी एग्रीकल्चर बिजनेस को लेकर समझ जुनून और क्षेत्र में कुछ कर गुजरने का जोश है तो आपको इस क्षेत्र में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है।

अदरक तेल उत्पादन

अगर आप कृषि पर आधारित हैं एग्रीकल्चर बिज़नेस आइडियाज संबंधित ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप अदरक के तेल का व्यवसाय के बारे में भी सोच सकते हैं। आजकल कई सारी बीमारियों के इलाज के रूप में अदरक के तेल का इस्तेमाल हो रहा है। जिसको बनाने के लिए ताजा और कच्ची अदरक का इस्तेमाल होता है और इसे कैंडी के रूप में पकाकर बनाया जाता है। वर्तमान समय में कई सारे आयुर्वेदिक पेय पदार्थों में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वह बॉडी स्लिम करने का आयल हो या कोई ऐसा लिक्विड हो जिससे लोग पी रहे हैं, अपने फैट को बर्न करने के लिए उसमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा है इसलिए इसकी मांग भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। शुरुआत में आपको इसका तेल निकालने के लिए एक मशीन लगाने की आवश्यकता है जिसकी सहायता से आप अदरक के तेल को निकाल सकें और उसका उत्पादन कर सकें।

सूरजमुखी तेल उत्पादन

सूरजमुखी का फूल देखने में जितना सुंदर होता है और और इसके बिजनेस मे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। आज गांव में बहुत सारे लोग सूरजमुखी के फूल की बहुत बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और जैसे -जैसे उसका फूल मुरझाने लगता है और पत्तियां झड़ जाती हैं तब तक उसका बीज भी पक चुका होता है। फूल के बीच का हिस्सा जो काफी चौड़ा और कठोर होता है वही होता है सूरजमुखी का बीज और उसी बीज से निकाला जाता है सूरजमुखी का तेल जिसका मार्केट प्राइस आम तेल के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। इसका तेल विटामिन ई की मात्रा का बहुत बड़ा स्त्रोत होता है विटामिन ई से संबंधित जो भी चीजें दवाई या अन्य चीजें बनती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो सिर्फ इसकी खेती करके इसके तेल को चक्की से भी निकलवा करके मार्केट में बेच सकते हैं।

सोयाबीन उत्पादन : आपने सोयाबीन की खेती के बारे मे तो जरूर सुना होगा और अब मार्केट में हरा सोयाबीन भी काफी बिकता है। यह सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि दूध पनीर बिस्कुट इत्यादि सभी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। अधिकतर महानगरों में सोया उत्पादों की मांग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए अधिकतर किसान भाइयों को सोयाबीन की खेती में बहुत फायदा हो रहा है। कुछ ऐसे भी है जो सोयाबीन को डायरेक्ट मार्केट में नहीं भेज रहे हैं बल्कि उसके अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं जिससे उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है।

गर्मियों में करें 3 सब्जियों की खेती और पाएं शानदार मुनाफा

कृषि डेस्क

मार्च का महीना इन तीनों सब्जियों की खेती के लिए आदर्श समय होता है. कम लागत में अधिक उत्पादन और गर्मी के मौसम में बढ़ी हुई मांग की वजह से किसान इन फसलों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मार्च का महीना खेती-किसानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह समय गर्मियों की फसल लगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस मौसम में कुछ विशेष सब्जियों की खेती करके किसान शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। गर्मी के मौसम में बाजार में इन सब्जियों की मांग काफी अधिक होती है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिलती है। यदि आप भी इस मौसम में खेती शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपको तीन ऐसी सब्जियों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी खेती से जबरदस्त मुनाफा हो सकता है.

लौकी की खेती

लौकी गर्मी के मौसम में खूब बिकने वाली सब्जी है। इसकी बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है और यह जल्दी तैयार होने वाली फसल है।

खेती की आवश्यकताएं - बुवाई का समय: मार्च से अप्रैल

मिट्टी का प्रकार: दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उत्तम रहती है।

सिंचाई: गर्मी में 5-7 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूरी है।

खाद एवं उर्वरक: जैविक खाद, गोबर खाद और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग करें।

कटाई-छंटाई: बुवाई के 50-60 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं।

लाभ : लौकी की फसल कम लागत में तैयार हो जाती है और उत्पादन अधिक होता है।

प्रति हेक्टेयर 300-400 क्विंटल तक उत्पादन संभव है।

बाजार में प्रति किलो 20-30 रुपये तक आसानी से मिल जाते हैं, जिससे अच्छा लाभ कमाया जा सकता है।

भिंडी की खेती

भिंडी भारतीय बाजार में गर्मियों के दौरान सबसे अधिक पसंद की जाने वाली सब्जियों में से एक है। यह कम लागत और कम पानी में भी अच्छी उपज देती है।

खेती की आवश्यकताएं- बुवाई का समय: फरवरी के अंत से अप्रैल तक भिंडी की खेती का समय है।

मिट्टी का प्रकार: अच्छी जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी बेहतर रहती है।

सिंचाई: 7-10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें।

खाद एवं उर्वरक: नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक खाद का संतुलित उपयोग करें।

कटाई-छंटाई: 40-45 दिनों में भिंडी की पहली तुड़ाई हो सकती है।

लाभ : भिंडी की फसल जल्दी तैयार होती है और 2-3 महीनों तक उत्पादन देती है। इससे प्रति हेक्टेयर 100-150 क्विंटल तक उपज मिल सकती है। बाजार में भिंडी की कीमत 30-50 रुपये प्रति किलो तक मिल सकती है, जिससे अच्छा मुनाफा होता है। इसकी खेती में कोई बड़ा नुकसान भी नहीं है।

खीरा की खेती

गर्मी के मौसम में खीरा की मांग बहुत अधिक रहती है। यह ताजगी भरी सब्जी होने के कारण लोग इसे सलाद और जूस के रूप में खूब इस्तेमाल करते हैं।

खेती की आवश्यकताएं- बुवाई का समय: मार्च से अप्रैल

मिट्टी का प्रकार: दोमट या बलुई मिट्टी सबसे अच्छी रहती है।

सिंचाई: गर्मी में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें।

खाद एवं उर्वरक: जैविक खाद और पोटाश, नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग करें।

कटाई-छंटाई: बुवाई के 40-45 दिनों बाद पहली तुड़ाई की जा सकती है।

लाभ : खीरे की फसल जल्दी तैयार होती है और बाजार में हमेशा अच्छी कीमत पर बिकती है। प्रति हेक्टेयर 150-200 क्विंटल तक उत्पादन हो सकता है। बाजार में इसकी कीमत 25-40 रुपये प्रति किलो तक मिल सकती है, जिससे किसानों को बड़ा मुनाफा मिलता है।

न्यू देहली पोस्ट

अमेरिका में बड़ा चुनावी रिफॉर्म, वोटिंग के लिए सिटीजनशिप प्रूफ अनिवार्य

इंटरनेशनल डेस्क

अमेरिका में बड़े स्तर पर चुनाव सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने देश के चुनावों में सुधार के लिए एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश में सख्त नियम शामिल हैं। जिसमें चुनावों में मतदान के लिए रजिस्टर कराने के लिए सिटीजनशिप प्रूफ देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही इसमें सभी बैलेट पेपर चुनाव के दिन तक उपलब्ध कराने की डिमांड भी शामिल है। ट्रंप की ओर से साइन किए गए आदेश में कहा गया है कि अमेरिका "बुनियादी और आवश्यक चुनावी सुरक्षा" को लागू करने में विफल रहा है। आदेश में राज्यों से मतदाता सूची साझा करने और चुनावी अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसियों के साथ काम करने का भी आह्वान किया है। इसके अलावा, इसमें उन राज्यों से फेडरल फंडिंग कम करने की धमकी दी गई है जहां अधिकारी अनुपालन नहीं करते हैं।

ट्रंप ने भारत, ब्राजील, डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों के उदाहरण भी दिए। भारत और ब्राजील द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये देश "मतदाता पहचान को एक बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए बड़े पैमाने पर स्व-सत्यापन पर निर्भर करता है।" एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए आदेश को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राज्यों को चुनावों के लिए अपने नियम निर्धारित करने का व्यापक अधिकार है। हालांकि, यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया की आलोचना करने के ट्रंप के इतिहास के अनुरूप है। ट्रंप ने अक्सर दावा किया है कि चुनाव में धांधली होती है, भले ही परिणाम घोषित न किए गए हों। 2020 के बाद से, ट्रंप कुछ मतदान मैथड को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि वे डेमोक्रेट जो बाइडेन से हार गए और उन्होंने व्यापक धोखाधड़ी को इसका कारण बताया। विशेष रूप से मेल वोटिंग पर फोकस करते हुए ट्रंप ने इसे असुरक्षित कहा है और कहा है कि यह धोखाधड़ी को आमंत्रित करता है। हालांकि, राष्ट्रपति ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है। मतदाताओं, जिनमें रिपब्लिकन भी शामिल हैं, के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए, ट्रंप ने अपने पिछले रुख से पीछे हट गए हैं और कहा है कि हालांकि धोखाधड़ी होती है, 'यह दुर्लभ है, दायरे में सीमित है, और मुकदमा चलाया जाता है।' मतदान के लिए नागरिकता दस्तावेजों के प्रमाण को अनिवार्य करने वाला आदेश दर्शाता है कि राष्ट्रपति अमेरिकी मतदाता पात्रता अधिनियम की सुरक्षा के लिए कांग्रेसी रिपब्लिकन के पारित होने का इंतजार नहीं करने वाले हैं, जिसका मकसद भी यही है।

हालांकि, वोटिंग राइट्स ग्रुप्स ने चिंता जताई है कि नागरिकता के प्रमाण की आवश्यकता मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकती है। ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस और अन्य समूहों की ओर से 2023 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मतदान की उम्र के नौ प्रतिशत, या 21.3 मिलियन, अमेरिकी नागरिकों के पास नागरिकता का प्रमाण आसानी से उपलब्ध नहीं है।इसके अलावा, विवाहित महिलाओं, जिन्होंने नाम बदल लिए हैं, को भी रजिस्टर कराने में परेशानी होने की संभावना है, क्योंकि उनके जन्म प्रमाण पत्र में उनका पहला नाम (मायके का नाम) लिखा होता है। अब चुकी राज्यों के पास चुनावों की अथॉरिटी है, इसके देखते हुए ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कुछ कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

एलएसी और कैलाश मानसरोवर पर दिल्ली -बीजिंग के बीच चर्चा

इंटरनेशनल डेस्क

भारत और चीन ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर स्थिति की व्यापक समीक्षा की। दोनों पक्षों ने सीमा पार सहयोग को शीघ्र बहाल करने पर जोर दिया। इसमें सीमा पार नदियों और कैलाश-मानसरोवर यात्रा पर सहयोग भी शामिल है। यह बातचीत बीते मंगलवार को की गई है। भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 33वीं बैठक के दौरान यह विचार-विमर्श हुआ। बैठक का आयोजन बीजिंग में हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव गौरांगलाल दास ने किया, जबकि चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा एवं महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक हांग लियांग ने किया।

बैठक के बाद जारी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, "समग्र द्विपक्षीय संबंधों के सुचारू विकास के लिए सीमा पर शांति और सौहार्द्र महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों ने दिसंबर 2024 में बीजिंग में भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों को प्रभावी बनाने और सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों और प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया।" इसमें कहा गया, "दोनों पक्षों ने इस दिशा में प्रासंगिक कूटनीतिक और सैन्य तंत्र को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। सीमा पार नदियों और कैलाश-मानसरोवर यात्रा सहित सीमा पार सहयोग और आदान-प्रदान को जल्द बहाल करने पर भी चर्चा

की गई।"

बैठक के दौरान, दोनों देशों ने विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक के लिए पर्याप्त तैयारी करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई, जो इस वर्ष के अंत में भारत में आयोजित की जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दोनों देशों के बीच 'विदेश सचिव-उप विदेश मंत्री तंत्र' की बैठक के लिए 26-27 जनवरी को बीजिंग का दौरा किया था। इसके बाद दोनों देशों ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। चर्चाओं के दौरान, विदेश सचिव मिसरी और चीनी उप विदेश मंत्री सन वेइदोंग ने संबंधों को स्थिर करने और पुनर्निर्माण के लिए कुछ जन-केंद्रित कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली-बीजिंग ने सैद्धांतिक रूप से दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की।

पाकिस्तान की रजिया सुल्तान बनी महरंग बलोच, पाक सेना बेदम

न्यू देहली पोस्ट

पाकिस्तान, जहां महिलाओं की आज़ादी पर पहरे बैठाए जाते हैं, वहीं एक महिला ने इस तानाशाही को खुली चुनौती दी है। नाम हैं डॉ. महरंग बलोच। महरंग ने पूरी पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम कर रखा है। महरंग के सामने पाक सेना बेदम है। पाकिस्तानी आर्मी जो विश्व में 12वीं सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है,जिसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई दुनिया की टॉप 10 में शामिल है.. आज वह महरंग बलोच के साहस के आगे बेदम नजर आ रही है। बेबस है। आखिर क्यों पाकिस्तानी सेना उनसे डर गई है ? पाक सेना बलोच से इतना डर गई है कि वह उसने बलोच को गिरफ्तार कर गायब कर दिया है ताकि जनता के सामने वह दिखे ही नहीं। आइए हम आपको बताते है कि आखिर कौन है महरंग बलोच ? महरंग बलोच का जन्म बलूचिस्तान के एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। पेशे से वह एक डॉक्टर हैं और उनकी पांच बहने और एक भाई हैं। उनके पिता अब्दुल गफ्फार बलोच एक मजदूर थे, जिनकी पाकिस्तानी सेना ने हत्या कर दी थी। उनके पिता को 2009 में पाकिस्तानी सेना ने कराची में उस वक्त अगवा किया था, जब वह एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हो रहे थे। जब पिता की हत्या की गई थी उस वक्त महरंग बलोच सिर्फ 16 साल की थी। 2011 में उनके पिता की लाश मिली थी जिस पर क्रूरता के गंभीर निशान मौजूद थे। उनके भाई को 2017 में सेना ने अपहरण किया था और तीन महीने तक गायब रखा था। उनके भाई को अधमरा स्थिति में रिहा किया गया था। पिछले कुछ सालों से डॉ महरंग , बलूचिस्तान में चलने वाले बलूच आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बन चुकी हैं।

दरअसल,पिछले साल, जब बलूच लोगों की हत्याओं और गायब किए जाने की घटनाएं बढ़ीं, तो महरंग बलोच ने ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च किया। 1600 किलोमीटर लंबा यह मार्च बलूचिस्तान के तुर्बत से इस्लामाबाद तक पहुंचा था। हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, महिलाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। तभी से महरंग बलोच पाकिस्तान सरकार और आर्मी की आखों में खटकने लगी। पाकिस्तान सरकार ने इनकी बात सुनने की बजाय, महरंग बलोच को ही गिरफ्तार करवा दिया। पाकिस्तानी सरकार महरंग बलोच को एक अलगाववादी बताती है। लेकिन महरंग बलोच का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह अहिंसक है, और ये सिर्फ मानवाधिकारों के लिए है। लेकिन पाकिस्तान की सेना बलूच युवाओं को आतंकी करार देकर उनकी हत्या कर रही है। सवाल ये है – कब तक? लेकिन सवाल सिर्फ महरंग बलोच के नहीं हैं। ये सवाल बलूचिस्तान के हर उस शख्स के हैं, जो अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान की सेना की इस बर्बरता पर कब लगेगी लगाम? हमें और आपको, पूरी दुनिया को इन सवालों का जवाब चाहिए!'' क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस मसले पर पाकिस्तान से जवाब मांगेगा?" लेकिन बड़ी बात तो यह है कि महरंग बलोच की चर्चा अब पाकिस्तान में भारत की रजिया सुलतान की तरह होने लगी है।

अब उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ उतरे फिलिस्तीनी

अब हमास के खिलाफ ही उत्तरी गाजा के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। वे युद्ध नहीं चाहते। वे शांति चाहते हैं ताकि अपनी जान को बचा सकें। इसमें शामिल होने लिए सैकड़ों फिलिस्तीनी सड़कों पर उतरे। उन्होंने युद्ध को समाप्त करने की मांग की और मांग की कि हमास सत्ता से हट जाए। ये प्रदर्शन गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में बेत लाहिया में हुए। इजरायली सेना द्वारा लगभग दो महीने के संघर्ष विराम के बाद गाजा पर अपनी गहन बमबारी फिर से शुरू करने के एक हफ्ते बाद भीड़ इकट्ठा हुई थी। 25 मार्च की देर रात सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो और तस्वीरों में सैकड़ों प्रदर्शनकारी, जिनमें ज्यादातर पुरुष थे, "बाहर, बाहर, बाहर, हमास बाहर" और "हमास आतंकवादियों" के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। उनके हाथों में प्ले कार्ड थे जिनपर "युद्ध बंद करो" और "हम शांति से रहना चाहते हैं" जैसे नारे लिखे हुए थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यहां नकाबपोश हमास उग्रवादी भी थे जिनमें से कुछ के पास बंदूकें और कुछ के पास डंडे थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जबरन तितर-बितर कर दिया और इस दौरान उनमें से कई पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया नेटवर्क टेलीग्राम पर विरोध में शामिल होने की अपील शेयर होने के बाद वे जमा हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने बताया, "मुझे नहीं पता कि विरोध प्रदर्शन किसने आयोजित किया था। " उसे डर था कि कहीं उससे बदला नहीं लिया जाएगा। इस डर से उसने अपना अंतिम नाम बताने से इनकार कर दिया। "मैंने लोगों की ओर से एक मैसेज भेजने के लिए इस प्रदर्शन में भाग लिया. युद्ध बहुत हो गया." उसने दावा किया कि हमास सुरक्षा बलों के सदस्यों को नागरिक कपड़ों में विरोध प्रदर्शन को तोड़ते हुए देखा था. एक अन्य प्रदर्शनकारी माजदी ने अपना पूरा नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, "लोग (युद्ध से) थक गए हैं.. अगर हमास का गाजा में सत्ता छोड़ना समाधान है, तो हमास लोगों की रक्षा के लिए सत्ता क्यों नहीं छोड़ देता?

अल्लू अर्जुन बने सबसे महंगे स्टार

अल्लू अर्जुन संदीप रेड्डी वांगा, वेणु श्रीराम, कोराताला शिवा और त्रिविक्रम के साथ उनकी फिल्मों में काम करने वाले थे। लाइन-अप अभी भी ट्रैक पर है या नहीं, यह एक्टर और उनकी टीम ही जानती है। हाल ही में अफवाहें उड़ी थीं कि अल्लू अर्जुन एक फिल्म के लिए एटली के साथ बातचीत कर रहे हैं। डील की बात भी सामने आ गई....

फ़िल्मी डेस्क

दक्षिण के सुपर स्टार अल्लू अर्जुन अब देश के सबसे महंगे स्टार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक अर्जुन ने एटली की एक फिल्म साइन की है। इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को 175 करोड़ फीस के रूप में मिलेंगे जबकि मुनाफे में भी 15 फीसदी की हिस्सेदारी होगी। खबर के मुताबिक़ एटली की फिल्म शानदार वीएफएक्स और वर्ल्ड-बिल्डिंग के साथ एक मेगा-बजट ब्लॉकबस्टर होने का वादा करती है। पुष्पा 2 की जबरदस्त सफलता के बाद अल्लू अर्जुन काफी महंगे स्टार होते जा रहे हैं।

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, "अल्लू अर्जुन ने मेकर्स सन पिक्चर्स के साथ 175 करोड़ रुपये की डील की है। साथ ही मुनाफे में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी की बैकएंड डील भी किया है। यह फिलहाल किसी भी एक्टर की साइन की गई सबसे बड़ी फ्रंट-एंड डील है, और अल्लू ने अगस्त 2025 से एटली और सन पिक्चर्स को बल्क डेट्स दी है। प्री-प्रोडक्शन में लगने वाले टाइम के हिसाब से अगस्त से अक्टूबर के बीच फिल्म को शुरू करने का विचार है।"

जानकारी के मुताबिक़ "सीन में सभी नएपन के बावजूद, कहानी में एक आइडल एटली फिल्म के सभी एलिमेंट्स होंगे। यह एटली और अल्लू अर्जुन दोनों के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। " बताया जा रहा है कि "पुष्पा जैसी सक्सेस के बाद हालात को मजबूत करने के लिए सही फिल्म के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। ए6 अल्लू के लिए आगे बढ़ने के लिए एकदम सही प्रोजेक्ट है। "

अल्लू अर्जुन संदीप रेड्डी वांगा, वेणु श्रीराम, कोराताला शिवा और त्रिविक्रम के साथ उनकी फिल्मों में काम करने वाले थे। लाइन-अप अभी भी ट्रैक पर है या नहीं, यह एक्टर और उनकी टीम ही जानती है। हाल ही में अफवाहें उड़ी थीं कि अल्लू अर्जुन एक फिल्म के लिए एटली के साथ बातचीत कर रहे हैं। डील की बात भी सामने आ गई लेकिन अल्लू और फिल्म मेकर ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है।

सिकंदर' में सलमान-रश्मिका का रोमांटिक अंदाज

फिल्मी डेस्क

सलमान खान उर्फ भाईजान ईद 2025 पर 'सिकंदर' के साथ बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए आ रहे हैं।30 मार्च को दुनिया भर के सिनेमाघरों में बॉलीवुड सुपरस्टार की फिल्म रिलीज होगी। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब, निर्माता ने ट्रेलर की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। सलमएआर मुरुगादॉस की डायरेक्टेड, साजिद नाडियाडवाल की प्रोड्यूस्ड 'सिकंदर' से सलमान खान और रश्मिका मंदाना का ट्रेलर रिलीज से पहले बेहद रोमांटिक पोस्टर सामने आया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'सिकंदर' का ट्रेलर भी सामने आ गया है। इस ट्रेलर में सलमान और रश्मिका एक-दूसरे की आंखों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों का ये रोमांटिक अंदाज सभी को बहुत पसंद आ रहा है। रश्मिका मंदाना पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर सलमान खान के साथ रोमांस करते नजर आएंगी।

सिकंदर' का निर्देशन एआर मुरुगादॉस ने किया है। फिल्म में काजल अग्रवाल, सत्यराज, प्रतीक बब्बर, अंजिनी धवन और नवाब शाह भी हैं। मुरुगादॉस को 'गजनी', 'थुप्पाक्की', 'हॉलिडेः ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी' और 'सरकार' जैसी फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। रश्मिका संग सलमान की फ्रेश पेयरिंग कमाल लगने वाली है।

सलमान की सिनेमाघरों में पिछली रिलीज टाइगर 3 थी जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 'सिकंदर' की एडवांस बुकिंग विदेश में शुरू हो गई है। वहीं 27 या 28 मार्च को भारत में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। फिल्म ने अमेरिका में 13 लाख रुपए की कमाई कर ली है।

आईपीएल में धाक जमाने उतरेगा ये आदिवासी खिलाड़ी

खेल डेस्क

झारखंड का जिला गुमला खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहां से फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स समेत कई खेलों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुके हैं। वहीं, अब तक क्रिकेट के क्षेत्र में गुमला गुमनाम था। लेकिन, अब यहां क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ने लगी है। इसका कारण रॉबिन मिंज हैं. पिछली बार आईपीएल ऑक्शन में गुमला का नाम पहली बार सामने आया। रायडीह प्रखंड के एक छोटे से गांव सिलम पांदनटोली के रहने वाले रॉबिन मिंज ने गांव से आईपीएल तक का सफर तय किया था। आदिवासी गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले रॉबिन के कामयाबी की चर्चा अब पूरे प्रदेश में है। एक आदिवासी खिलाड़ी का क्रिकेट में यहां तक पहुंचना माने रखता है. लेकिन, ये सफर इतना आसान नहीं था।

रॉबिन मिंज के भाई कहते हैं कि रॉबिन का बचपन से ही क्रिकेट के प्रति रुझान गजब का था। जब वह 7-8 साल का हुआ, तो उस समय क्रिकेट का रुझान और बढ़ गया। हम लोगों का आशीर्वाद और विश्वास है कि वह देश के लिए अच्छा खेले और आगे बढ़े। पिताजी जेवियर मिंज फौज में जॉब करते थे, तो हम लोग रांची नामकुम चले गए। फिर वहीं रहकर रॉबिन ने पढ़ाई के साथ-साथ क्रिकेट का अभ्यास भी किया। वहीं, गांव के लालमोहन लोहरा ने बताया कि रॉबिन ने गांव के अन्य बच्चे के साथ खाना बनाने वाली लकड़ी से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। जैसे गांव के अन्य बच्चे प्लास्टिक व टेनिस बॉल और लकड़ी के बल्ले से क्रिकेट खेलते थे। उसी तरह वह भी खेलता था. आईपीएल स्टार्ट हो रहा है और हमारे गांव के रॉबिन मिंज मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वह इस बार आईपीएल में अच्छा खेलेगा और लंबे-लंबे शॉट मारेगा। भारतीय क्रिकेट टीम में भी शामिल होगा।

बता दें, रॉबिन मिंज को पिछले आईपीएल ऑक्शन में गुजरात टाइटंस की टीम ने तीन करोड़ 60 लाख में खरीदा है। लेकिन, दुर्भाग्य से सड़क दुर्घटना में चोटिल होने के कारण रॉबिन पिछले साल आईपीएल सत्र में नहीं खेल पाए थे। इस बार उम्मीद है जरूर खेल पाएंगे। इस बार आईपीएल की सबसे सफल टीमों में शुमार मुम्बई इंडियंस की टीम ने रॉबिन के लिए 65 लाख की बोली लगाई है। रॉबिन मिंज विस्फोटक बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग के लिए जाने जाते हैं। बिन मिंज पहले आदिवासी क्रिकेटर हैं, जो IPL खेलते नजर आएंगे।

पत्रकारिता को नए सिरे से परिभाषित करते हुए न्यू देहली पोस्ट की शानदार प्रस्तुति अब आपके सामने है। इसमें होगी खोजी और जानबूझ कर दबाई गई ख़बरों के उद्भेदन की शानदार प्रस्तुति - न्यू दिल्ली पोस्ट प्रिंट और डिजिटल के सभी मंचो के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है :-

न्यू देहली पोस्ट
(साप्ताहिक हिंदी)

हमारे ये सभी डिजिटल मंच सभी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। यहाँ जाकर आप ताजातरीन ख़बरों और विश्लेषण को देख समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं।

Website: https://newdelhipost.co.in/
: @NewDelhiPost
: https://www.facebook.com/NewDelhiPosts
: @NewDelhiPost
:newdelhipost_official

न्यू देहली पोस्ट
B-614, 6th Floor Tower B
Noida One Building
Noida Sector 62, Gautam Budh Nagar (UP)
Pin Code -201309

संपर्क करे - Email - postnewdelhi@gmail.com